स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–1, पौष– 2067, जनवरी 2011

झारखण्ड विशेषांक

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-6

राजीव गांधी के जीवन का राजनीतिक सार यही था कि यदि आप ईमानदार नहीं हो तो ईमानदार होने का दावा मत करो। पर अफसोस राजीव के जीवन का सबक खुद सोनिया गांधी ही भूल गईं।

कवर पेज

अनुक्रम

आवरण लेख
चुप्पी कहीं स्वीकारोक्ति तो नहीं!
– एस. गुरुमूर्ति /6

प्रतिक्रिया
ईमानदार पर भ्रष्टाचार और महंगाई भारी
– विक्रम उपाध्याय /11

महंगाई
भ्रष्टाचार और कीमतें सरकार की नहीं सुनती
– आलोक पुराणिक /13

विशेषांक
स्वदेशी जागरण मंच (बोकारो) /17

पर्यावरण
नदी एवं पारिस्थितिकी
– कौशल किशोर शर्मा /21

रपट : नदियां ही नहीं बचेंगी तो मानव अस्तित्व भी नहीं बचेगा /24

कृषि
परंपरागत ज्ञान से ही होगा किसान का विकास
– देविंदर शर्मा /25

विचार–विमर्श
नीतिश ने दिखायी नयी राह
– निरंकार सिंह /28

मुद्दा
नेक उद्यमी पर भी सरकार का अंकुश जरूरी
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /31

लेख
स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थित
– रेणु पुराणिक /34

पाठकनामा/2, तिरछी नज़र/5

रामराज्य बनाम गाँधी

स्वदेशी पत्रिका का अक्टूबर 2010 अंक मैंने पढ़ा। इसमें सभी लेख उत्तम और देश की सबसे बड़ी समस्या ग्रामोत्थान पर विशेष ध्यान दिलाने वाले थे। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। इस पत्रिका की उन्नति और विकास की ईश्वर से कामना है।

आवरण कथा के अंदर यह वाक्य ''राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी रामराज्य की व्यवस्था के प्रबल आग्रही थे – अखर गया। क्योंकि यह सत्य से बिलकुल विपरीत है। मुझे याद है कि सन् 1946 अथवा 1947 में एक पत्रकार ने गांधी जी से प्रश्न किया, ''आप भारत विभाजन के प्रबल विरोधी है यानि पाकिस्तान की अवधारणा के विरुद्ध हैं, किन्तु समस्त भारत के लिए आप रामराज्य के समर्थक हैं। ऐसे में मुसलमान भारत में कैसे सुखी रह सकते हैं?'' गाँधी जी ने उत्तर दिया, ''मेरे रामराज्य का अर्थ अयोध्या वाला रामराज्य नहीं है। मेरा अर्थ है 'निज़ामे मुस्तफा', 'किंगडम ऑफ गॉड'। इसमें निज़ामे मुस्तफा का अर्थ है – कुरान सम्मत इस्लामी राज्य और किंगडम आफ गॉड (ईश्वरीय राज्य) का अर्थ है ईसाईमत के वर्चस्व वाला राज्य।

साथ ही ''आस्था के साथ राम की व्यवस्था करने का समय'' में तो अयोध्यापति श्रीराम की ही राज्य व्यवस्था वर्णित है, जिसके किसी भी बिन्दु का उल्लेख गाँधी जी ने नहीं किया। मेरे हिसाब से गाँधी जी श्रीराम को ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं मानते थे।

– रामगोपाल (स्वतंत्र लेखक और पत्रकार),
ए–2बी/94ए, एकता अपार्टमेंट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063

घोटाले जिंदाबाद, महंगाई अमर रहे

मैं काफी समय से स्वदेशी पत्रिका पढ़ रहा हूँ। पत्रिका द्वारा राजनीतिक पार्टियों के कार्य–कलापों का लेखकों द्वारा बयान किया गया है। इससे साबित होता है कि इन राजनेताओं को सिर्फ वोट चाहिए। आम मतदाताओं को इन्होंने महंगाई के जाल में इस तरह उलझा दिया है कि उसे सिर्फ नमक, तेल, धनिया, आटा, चीनी, चावल, प्याज, टमाटर के अलावा सोचने की शक्ति गायब कर दी है। बची खुची सोचने की शक्ति एल.पी.जी. (गैस सिलेण्डर) खा गयी। मतदाताओं को देश के भले–बुरे के संबंध में सोचने का समय ही नहीं रहा है। आज देश में खाने–पीने की चीजों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं।

देश में जितने भी घोटाले हो रहे हैं उनमें इन्हीं सफेदपोश नेताओं और सरकारी अफसरों का हाथ होता है। आज कश्मीर के हालात बेकाबू से बाहर हो रहे है। साथ ही माओवादियों ने एक बड़े क्षेत्र पर खुद की सत्ता स्थापित कर ली है। सी.आर.पी.एफ. के जवान सशस्त्र विद्रोह की बलि चढ़ रहे हैं।

ये सब समस्याएं वर्तमान यूपीए सरकार की कमजोरी को दर्शाती हैं। इन सभी कारणों को पढ़कर काफी दुःख होता है। ऐसा लगता है आज की सरकार मुगलों व अंग्रेजों से भी खरतनाक हो चुकी है।

– भुवनेश कुमार त्यागी, 510 साकेत मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

कांग्रेस की स्थापना का 125वां साल संप्रग के लिए घोटालों का वर्ष रहा। हर महीने एक नए घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

– नितिन गड़करी,
अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

आर्थिक मंदी के दौर से निपटने में केंद्र सरकार ने जो राहत प्रदान किया। उससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी।

– प्रणब मुखर्जी
वित्त मंत्री, भारत सरकार

तेलंगाना के लोग तेलंगाना से कम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे जिसकी राजधानी हैदराबाद होगी।

– के. चंद्रशेखर राव,
तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख

बोफोर्स पर झूठ बेनकाब

बोफोर्स का जिन्न फिर बाहर। कई घोटालों में फंसी कांग्रेस के लिये बोफोर्स एक बार फिर से सिरदर्द बनने वाला है। इस बार किसी राजनैतिक दल ने कोई नया आरोप नहीं लगाया है। बल्कि केन्द्रीय आयकर विभाग ने तमाम सबूतों के आधार पर निर्णय सुनाया है। कि बोफोर्स की दलाली ने बिनचड्ढा और क्वात्रोच्चि को लगभग 64 करोड़ रूपये की दलाली मिली।

आयकर विभाग ने अपने दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि दलाली के लिये 1986 में एक कंपनी बनायी गयी और उसमें भारत सरकार द्वारा भुगतान किये जाने के बाद दलाली की रकम डाली गयी। बाद में इसी रकम को स्विस बैंक के खाते में जमा किया गया। अभी तक कांग्रेस और उसकी सरकार यही कहती हुयी आ रही थी कि बोफोर्स के मामले में कोई दलाली नहीं दी गयी और क्वात्रोच्चि से कांग्रेस सदस्या सोनिया गांधी का कोई संबंध नहीं था। हालांकि इस मसले पर सीबीआई ने अलग–अलग समय पर अलग–अलग मामले दर्ज किये और उसकी जांच की। पर अभी पिछले साल ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर यह अनुमति मांगी थी कि बोफोर्स दलाली की जांच को बन्द करने की अनुमति दी जाये। उसके पहले सीबीआई ने क्वात्रोच्चि के खिलाफ कोई सबूत न होने का दावा किया था और लंदन में जब्त उसके खाते को खोल देने का अनुरोध वहां की सरकार से किया था।

अब केन्द्र सरकार के एक विभाग द्वारा दलाली के सबूत पेश किये जाने के बाद कांग्रेस सकते में है और वह अब ठीकरा सीबीआई पर फोड़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि सीबीआई चाहे तो नये सिरे से मामला दर्ज कर सकती है। एक तथ्य और सामने आया कि भारत सरकार को भी तभी मालूम था कि बोफोर्स कंपनी ने बिनचड्ढा को एक बिचौलिये की भूमिका में रखा हुआ है। जबकि भारत ने किसी भी रक्षा सौदे को लेकर किसी बिचौलिये की भूमिका मान्य नहीं है। कांग्रेस अब भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब भाजपा में भी भ्रष्टाचार के आरोप से दे रही है। देश को यह बताने के लिये कि कांग्रेस बेहद मुश्किल स्थिति का सामना कर रही है कि आखिर 25 साल बाद भी क्वात्रोच्चि और बिनचड्ढा को दी गयी दलाली का भंडाफोड़ क्यों नहीं हुआ?

देश में विदेशी बैंकों को लेकर जिन लोगों ने भी यह दलील दी थी कि देश की बैंकिंग सेवा में सुधार आयेगा और ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। उनके लिये सिटी बैंक के कारनामे आंख खोलने के लिये एक और उदाहरण है। गुड़गांव स्थित सिटी बैंक की एक शाखा में 400 करोड़ रूपये का घोटाला हो गया और किसी को कानो–कान खबर नहीं हुआ। यह बैंकिंग प्रणाली के ध्वस्त होने का प्रमाण है। किस तरह से एक बैंक का अधिकारी कुछ कॉरपोरेट घरानों को साथ मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है।

इसका ताजा नमूना है सिटी बैंक का यह घोटाला। यह कुछ खाताधारकों को बरगलाकर उनके पैसे इधर–उधर लगाने का ही मामला नहीं है बल्कि अभी तक की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि सिटी बैंक का वह अधिकारी एक खास कॉरपोरेट घराने के पैसे से शेयर बाजार को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है कि घोटाले की इस रकम से उन शेयरों को चढ़ाने या उतारने का उपक्रम चल रहा था। जिनमें इन कंपनियों की व्यक्तिगत रूचि थी। एक तरह से छोटे निवेशकों को फंसाकर उनकी पूंजी ऐंठने की यह कोशिश थी। सिटी बैंक का यह कांड दूसरा हर्षद मेहता कांड के रूप में सामने आ सकता है क्योंकि शेयरों को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने के लिये यहां भी शेयर दलालों का एक गुट सक्रिय था।

RKFL

RAMKRISHNA Forgings Limited

Plant-III & IV, Plot No. M-15, 16 & NS-26, Phase-VII, Industrial Area, Adityapur, Jamshedpur-832 109, Jharkhand (India)

Ph.: 0657-3984999, Fax: 0657-3984998, E-mail: cnc-division@ramkrishnaforgings.com

TÜV NORD

TÜV NORD Iran PJS

ISO/ TS 16949

Regd. & Corporate Office

L&T Chambers, 6th Floor, 16, CAMAC Street, Kolkata - 700 017
West Bengal (India), Phone: (+91 33) 3984 0999, Fax: (+91 33) 3984 0998
E-mail : info@ramkrishnaforgings.com

Works

Plant-I, Plot No. M-6, Phase-VI, Gamharia, Jamshedpur - 832 108, Jharkhand
Phone: (+91 657) 3204242, 3204249, Fax: (+91 657) 2202814,
Email: forgings-division@ramkrishnaforgings.com

Plant-II, 7/40, Duffer Street, Liluah, Howrah - 711204, W.B.
Phone: (+91 33)2654 3385, Fax: (+91 33) 2654 5729

Website: www.ramkrishnaforgings.com

तिरछी नज़र

दिग्विजय सिंह होने के मायने

कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह आजकल मीडिया में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी ज्यादा छाये हुए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्यों? उनके पास एक ही एजेन्डा है और वह यह कि किसी भी तरीके से हिन्दू आतंकवाद की नई अवधारणा को स्थापित करें। इसके लिये वे उस हर राजनीतिक सीमा को लांघने के लिये तैयार हैं। जहां पर यह माना जाता है कि कोई नेता खुद को लाइमलाइट में लाने के लिये कोई भी हथकण्डा अपनाने के लिये तैयार है। दिग्विजय सिंह कोई छुटभैया नेता नहीं है। लाइमलाइट में रहने की उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है। वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में उनकी ऊँची पैठ है। उ0प्र0 जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस को स्थापित करने का उन्हें जिम्मा दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें राहुल गांधी का राजनीतिक सलाहकार माना जाता है। फिर यह सोचना कि दिग्विजय सिंह हिन्दू आतंकवाद की अवधारणा को स्थापित करने का अभियान व्यक्तिगत तौर पर चला रहे हैं, नासमझी की बात होगी। कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकती। मुस्लिम वोट के लिये हिंदुओं के वोट को तिलांजलि देने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर सकती। फिर दिग्विजय सिंह का अनर्गल बयान कांग्रेस अध्यक्ष क्यों बर्दाश्त कर रही है। कई ऐसे मौके आये जब मीडिया ने यह जानना चाहा कि देश के लिये बलिदान देने वाले महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी हेमन्त करकरे के बारे में दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना–देना है कि नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने चुप्पी साधकर भ्रम की स्थिति बनाये रखी। जब कांग्रेस के दिल्ली अधिवे ान के दौरान राहुल गांधी ने भी हिन्दू आतंकवाद से देश पर खतरा के रागअलापे तो भाायद किसी को यह भ्रम अब नहीं रहा कि दिग्विजय सिंह जो कुछ भी कह और कर रहे हैं, कांग्रेस उससे अलग विचार नहीं रखती। कांग्रेस के अंदर भी यह रणनीति बन रही है कि हर मोर्चे पर विफल होने और नेताओं के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद जनता का ध्यान हटाने के लिये उसके पास क्या बेहतर विकल्प हैं? मंहगाई, भ्रष्टाचार और राजनैतिक अनैतिकता को ढंकने के लिये कांग्रेस को कुछ ऐसी सनसनी चाहिए जिसे मीडिया में आसानी से भुनाया जा सके और जिसकी आड़ लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी को खामोश रखने का प्रयत्न किया जा सके। इस काम के लिये कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह जैसे नेता से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता था? अच्छी हिन्दी और अंग्रेजी बोलने वाले वाकपटु और लोगों से घुलमिल जाने वाले दिग्विजय सिंह कांग्रेस के इस प्रपोगण्डा को आसानी से बढ़ा सकते थे। इसलिये यह काम उन्हीं

को सौंपा गया। बाटला हाउस काण्ड को दिग्विजय सिंह ने पहला हथियार बनाया और यह कहकर सनसनी फैला दी कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गये लोग आतंकवादी नहीं भारीफ थे और उन्हें एनकाउंटर में नहीं बल्कि सोच समझकर मारा गया। दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस काण्ड पर सवाल खड़े कर उ0प्र0 के मुसलमानों की हमदर्दी खरीदने की कोशिश की। वह इसे और पुख्ता करने के लिये आजमगढ़ गये जहां से पिछले कुछ सालों में कई ऐसे नाम निकले जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में भाामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन मिला और अच्छी संख्या में लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब रही। संभवतः आतंकवादी घटनाओं के लिये पूरे विश्वभर में इस्लाम से जुड़े लोगों के नाम आने के बाद एक तरह से धारणा बनने लगी कि विश्व में इस्लामिक आतंकवाद का बोलबाला हो गया है। भारत में भी घटी तमाम आतंकवादी घटनाओं के पीछे लगे जितने भी चेहरे सामने आये उनमें अधिकतर मुसलमान ही थे। धीरे–धीरे भारतीय जनमानस भी पश्चिम द्वारा इस्लामी आतंकवाद की अवधारणा को मानने लगा। हालांकि राजनैतिक रूप से इस अवधारणा का विरोध किया गया लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनैतिक रूप में भुनाने का फैसला किया। कांग्रेस यह खतरा नहीं उठा सकती थी कि इस्लामी आतंकवाद के सामने हिन्दू आतंकवाद की अवधारणा नेतृत्व के स्तर से उठाती। इसलिये कुछ ऐसे लोग खड़े किये गये जिनके सहारे इस नये राजनैतिक हथकण्डे को आजमाया जा सके। दिग्विजय सिंह का पहला प्रयोग सफल था। इसलिये यह जिम्मेदारी उन्हीं को दी गयी। जब–जब विपक्ष ने मनमोहन सिंह की सरकार पर हल्ला बोला, तब–तब दिग्विजय सिंह ने उसको कमजोर करने के लिये हिन्दू आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जब 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर विपक्ष ने संसद ठप किया, बोफोर्स दलाली को लेकर प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा किया तब दिग्विजय सिंह ने भी हिन्दू आतंकवाद का मुद्दा अलग–अलग ढंग से उठाया, कभी उन्होंने करकरे से हुये अपनी फोन वार्ता को हथियार बनाया तो कभी यह बयान देकर मीडिया में बड़ी जगह पायी कि देश में हुए सभी विस्फोटों के लिये हिन्दू आतंकवादी जिम्मेदार हैं। उन्होंने मालेगांव का जिक्र किया, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस का जिक्र किया, उन्होंने हेमन्त करकरे का जिक्र किया और सबको शिवसेना एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ दिया। मीडिया के लिये यह सनसनी थी। मीडिया ने उनके बयानों को परखे बिना उसकी टाइमिंग की परीक्षा किये बिना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता को जांचे बिना दिग्विजय सिंह को खूब महत्व दिया। कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्टाचार और मंहगाई के लिये कटघरे में खड़ा करने के साथ–साथ संघ और भाजपा को भी अनर्गल मामलों में भी जवाब देने के लिये उत्तरदायी बनाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि दिग्विजय सिंह अपनी योजना में अब तक सफल रहे हैं। उनके सहारे कांग्रेस भी विपक्ष के हमले की धार को कमजोर करने में सफल रही है। मकसद देश को गुमराह कर अपनी खाल बचाये रखना था, जिसमें फिलहाल कांग्रेस सफल रही और दिग्विजय सिंह का होना सार्थक रहा।

स्विस बैंक में खाते और के.जी.बी. से रिश्वत के खुलासे के बाद भी कांग्रेस खामोश

चुप्पी कहीं स्वीकारोक्ति तो नहीं!

राजीव गांधी के जीवन का राजनीतिक सार यही था कि यदि आप ईमानदार नहीं हो तो ईमानदार होने का दावा मत करो। पर अफसोस राजीव के जीवन का सबक खुद सोनिया गांधी ही भूल गईं।

■ एस. गुरुमूर्ति

राजीव गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी गलती क्या थी? बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने खुद को पाक साफ और ईमानदार नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की, जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन के लिए खतरनाक साबित हुई।

ठीक इसके विपरीत उनकी मॉ श्रीमती इंदिरा गांधी ईमानदारी से यह स्वीकार करती थी कि भ्रष्टाचार से वह अलग नहीं है। बल्कि उन्होंने 1983 में यहां तक कहा कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, और यह पूरे विश्व में व्याप्त है। तब दिल्ली के ईमानदार जज ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, जब प्रधानमंत्री पद पर बैठी शख्सियत इसे सामान्य घटना के रूप में प्रभावित करती है। लेकिन श्रीमती इंदिरागांधी की स्वीकारोक्ति के बाद किसी ने भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि वह ईमानदार हैं।

लेकिन राजीव गांधी में खुद को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का धुन सवार था। इस कारण उनके हर किए की परख की जाने लगी और उसकी परिणती 1989 में हुई, जब बोर्फोस दलाली के आरोप के कारण जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

श्रीमती इंदिरा गांधी ईमानदारी से यह स्वीकार करती थी कि भ्रष्टाचार से वह अलग नहीं है। बल्कि उन्होंने 1983 में यहां तक कहा कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, और यह पूरे विश्व में व्याप्त है. . .लेकिन श्रीमती इंदिरागांधी की स्वीकारोक्ति के बाद किसी ने भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि वह ईमानदार हैं।

राजीव गांधी के जीवन का राजनीतिक सार यही था कि यदि आप ईमानदार नहीं हो तो ईमानदार होने का दावा मत करो। पर अफसोस राजीव के जीवन का सबक खुद सोनिया गांधी ही भूल गईं।

अब सवाल यह उठता है कि क्या 1987 व 1989 का इतिहास इस बार फिर दुहराया जाएगा।

इंदिरा गांधी को भूल राजीव गांधी की शैली अपनाने वाली सोनिया गांधी एक बार फिर वही भूल कर रही हैं। उन्होंने

नवंबर में इलाहाबाद में आयोजित एक रैली में गरजते हुए कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके एक हफ्ते बाद दिल्ली अधिवेशन में उन्होंने फिर कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को आह्वाण किया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे संघर्ष करें। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि उनकी पार्टी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही से जरा भी चूकना नहीं चाहती क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण विकास अवरूद्ध होता है।

सोनिया गांधी की ही तरह राजीव गांधी ने 25 साल पहले मुंबई के अधिवेशन में भी यही कहा था। वे मिस्टर क्लीन की छवि चाहते थे। जिस समय उन्होंने ईमानदार होने का दावा किया था तब उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं चल रहा था। लेकिन आज जब सोनिया गांधी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी नेता के रूप में सिद्ध करने में लगी हैं तो ठीक इसके विपरीत बड़े–बडे घोटाले सामने आये हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, 2जी स्पैक्ट्रम के घोटाले आदि–आदि।

जब राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी तो उनके सामने साफ माहौल था। इसके उलट सोनिया गांधी की हालत जवाब देने लायक नहीं है। स्विस बैंक के उनके एकाउंट के उजागर होने के बाद ईमानदारी की छवि पर बट्टा लग चुका है। बोफोर्स घोटाले में सिर्फ क्वात्रोच्चि ने ही करोड़ों डॉलर के रिश्वत नहीं लिये बल्कि राजीव गांधी का परिवार भी घोटाले में हिस्सेदार रहा। आज तक सोनिया गांधी ने मशहूर स्विस पत्रिका और रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के खुलासे का खंडन नहीं किया।

इंदिरा गांधी को भूल राजीव गांधी की शैली अपनाने वाली सोनिया गांधी एक बार फिर वही भूल कर रही हैं। उन्होंने नवंबर में इलाहाबाद में आयोजित एक रैली में गरजते हुए कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके एक हफ्ते बाद दिल्ली अधिवेशन में उन्होंने फिर कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को आह्वाण किया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे संघर्ष करें।

सोनिया गांधी का स्विस बैंक में कोई एकाउंट है और उसमें करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि स्विटरजरलैंड की एक पत्रिका ने ही किया। 19 नवम्बर, 1991 को अपने अंक में स्विस पत्रिका स्विट्ज़र इलस्ट्रेट ने तीसरी दुनिया के दर्जनों ऐसे राजनेताओं के खातों का ब्यौरा दिया जिसमें करोड़ों डॉलर पड़े हुए थे।

इन नेताओं में राजीव गांधी का भी नाम था, जिन्होंने बोफोर्स तोप के सौदे के बाद मिली दलाली का हिस्सा उस एकाउंट में डाल रखा था। स्विटजरलैंड की इस पत्रिका के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह स्विटजरलैंड से प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका है।

उस समय उसकी 2,15,000 प्रतियां बिकती थीं और 10 लाख से अधिक पाठक थे। इस पत्रिका ने केजीबी के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी ने अपने नाबालिग बेटे के नाम पर स्विस बैंक में एक गुप्त एकाउंट खोल रखा है, जिसमें 2.5 अरब स्विस फ्रेंक जमा है जो लगभग 2.2 अरब डॉलर के बराबर होता है। यह 2.2 अरब डॉलर कम से कम 1988 तक उस एकाउंट में जरूर रहा होगा जब राहुल गांधी 18 वर्ष के हुए होंगे।

अगर उस समय के इस घोटाले के पैसे का आज की दर से आंकलन करें तो यह रकम 10 हजार करोड़ रूपये के बराबर होती है। जाहिर है स्विस बैंक इन गुप्त खातों में जमा धन का इस्तेमाल अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में करता होगा। कल्पना करिये यदि वही पैसा किसी सुरक्षित दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूति में निवेश किया गया होता तो आज वह पैसा 42,345 करोड़ रूपये के बराबर होता। यदि वह पैसा अमेरिका के शेयर बाजार में लगा होता तो आज वह बढ़कर 58,365

करोड़ रूपये के बराबर हो गया होता। यदि दीर्घावधि बॉण्ड और शेयर बाजार में लगा होता तो वह पैसा 83,900 करोड़ रूपये के बराबर हो जाता। राजीव गांधी के परिवार द्वारा स्विस बैंक में वह जमा घोटाले की राशि आज की दर से कहीं भी 43 हजार करोड़ से लेकर 84 हजार करोड़ रूपये के बीच होती।

केजीबी के हवाले से रूसी पत्रकार येवजेनिया अल्बैट्स ने तो राजीव गांधी परिवार पर और गंभीर आरोप लगाए। अपनी पुस्तक द स्टेट विद इन स्टेटः द केजीबी एंड इट्स होल्ड ऑन रसिया– पास्ट, प्रेजेन्ट एंड फ्यूचर में इस खोजी पत्रकार ने 1982 में एन्द्रोपो की जगह केजीबी के मुखिया बनने वाले विक्टर चेब्रिकोव के एक हस्ताक्षर युक्त पत्र को उद्घृत करते हुए लिखा कि सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी ने राजीव गांधी के परिवार से लगातार संपर्क बनाये रखा।

पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि गांधी परिवार का एक सदस्य रूसी नेताओं को इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि रूस के साथ हुए व्यवसायिक समझौते से पूर्व प्रधानमंत्री परिवार को आर्थिक लाभ मिलता रहा है।

रूस से जिन लोगों के नाम से पैसे मिले, उनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सोनिया गांधी की मां पाओला मेनिया शामिल हैं। इस रूसी पत्रकार ने अपने खुलासे में यह भी लिखा कि केजीबी से

जून, 1988 के बाद, जबसे स्विस पत्रिका और केजीबी ने राजीव गांधी परिवार के स्विस खाते का ब्यौरा दिया, कभी भी गांधी परिवार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनकी खामोशी ही स्वीकारोक्ति है।

प्राप्त पैसे का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने खूब किया।

रूसी पत्रकार की इस पुस्तक का अंश 4 जुलाई, 1992 को हिन्दू अखबार में भी छपा। द हिन्दू ने लिखा– ''रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी ने यह स्वीकार किया है कि केजीबी ने राजीव गांधी के परिवार द्वारा संचालित कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये सोवियत रूस की कंपनियों से करार करवाया।

राजीव गांधी के असमय निधन के कारण सोनिया गांधी के स्विस बैंक से संबंध उजागर नहीं हुए लेकिन भारतीय मीडिया का एक वर्ग इस खोजबीन में लगा रहा। भारत के एक मशहूर स्तंभकार ए.जी. नूरानी ने दि स्टेट्समेन अखबार में स्विट्जर इलस्ट्रैट और अलबेट्स द्वारा किये गये घोटाले के पर्दाफाश को यहां छापा। जनता पार्टी के नेता सुब्रमनियन स्वामी ने भी स्विस पत्रिका और अलबेट्स के मुख्य अंश अपने बेबसाइट्स के जरिये लोगों को भेजे।

स्वामी ने स्विस पत्रिका से प्राप्त उस मेल का भी जिक्र किया है जिसमें पत्रिका ने कहा है कि नवम्बर, 1991 में उसने राजीव गांधी के नाम का खुलासा किया था जिनके खाते में 2.5 अरब स्विस फ्रेंक जमा थे। पत्रिका के संपादक ने सुब्रमियन स्वामी को यह भी कहा था कि वह चाहें तो पत्रिका की मूल प्रति भी भेज सकते हैं।

मैंने 29 अप्रैल, 2009 को दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख के जरिये इन सारे साक्ष्य को एक बार फिर उठाया क्योंकि 27 अप्रैल, 2009 को मैंगलोर में सोनिया गांधी ने अपने एक भा ाण में कहा था कि कांग्रेस स्विस बैंक में जमा काले धन के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने जा रही है। मैंने अपने लेख में सोनिया गांधी से पूछा था कि स्विस बैंक में उनके व उनके परिवार के एकाउंट में जमा पैसे का क्या करने जा रही हैं?

हाल ही में 27 दिसम्बर, 2010 के इंडिया टुडे के अंक में मशहूर अधिवक्ता रामजेठ मलानी ने भी स्विस पत्रिका और केजीबी के खुलासे का हवाला देते हुए

स्वामी ने स्विस पत्रिका से प्राप्त उस मेल का भी जिक्र किया है जिसमें पत्रिका ने कहा है कि नवम्बर, 1991 में उसने राजीव गांधी के नाम का खुलासा किया था जिनके खाते में 2.5 अरब स्विस फ्रेंक जमा थे। पत्रिका के संपादक ने सुब्रमियन स्वामी को यह भी कहा था कि वह चाहें तो पत्रिका की मूल प्रति भी भेज सकते हैं।

कांग्रेस से पूछा था कि राजीव गांधी परिवार के स्विस बैंक एकाउंट में जमा धन कहां है? सीपीआई एनके सांसद अमल दत्ता ने 7 दिसम्बर, 1991 को राजीव गांधी के स्विस बैंक के खाते का मुद्दा संसद में उठाया था लेकिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने संसद की कार्यवाही से राजीव गांधी का नाम हटवा दिया।

जून, 1988 के बाद, जबसे स्विस पत्रिका और केजीबी ने राजीव गांधी परिवार के स्विस खाते का ब्यौरा दिया, कभी भी गांधी परिवार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनकी खामोशी ही स्वीकारोक्ति है। जब स्विस पत्रिका ने यह आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपने नाबालिग बेटे राहुल गांधी के नाम पर स्विस बैंक में दलाली के पैसे जमा किये हैं तब न तो सोनिया गांधी ने और न ही राहुल गांधी ने इस मामले में कोई खंडन जारी किया, न उन्होंने इन साक्ष्यों के आधार पर भारतीय मीडिया में लिखे गये लेखों को कोई नोटिस जारी किया। न उन्होंने सुब्रमियन स्वामी को इस बात के लिये कोई नोटिस भेजा कि उन्होंने अपने बेबसाइट्स पर राजीव गांधी परिवार के स्विस बैंक के एकाउंट का ब्यौरा दिया है, न उन्होंने मुझे कोई सम्मन जारी किया। जब द हिन्दू और द टाइम्स आफ इंडिया ने केजीबी के हवाले से मिली खबर के आधार पर रूसी पत्रकार की पुस्तक का अंश छापा जिसमें यह कहा गया था कि गांधी परिवार ने केजीबी से लगातार आर्थिक सहायता ली तब भी सोनिया और उनके सलाहकार खामोश रहे।

कुछ अनिवासी भारतीयों ने रूसी पत्रकार अलबेट्स की पुस्तक के अंश को 2007 में न्यूयॉर्क टाइम्स के पूरे पेज पर विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करवाया तब सोनिया गांधी के एक समर्थक ने अमेरिकी अदालत में एक याचिका दायर की कि सोनिया गांधी का नाम इससे बदनाम होगा। अमेरिकी अदालत ने इस आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह याचिका सोनिया गांधी ने अपनी ओर से दाखिल नहीं करवायी थी। मजे की बात यह है कि उस याचिका में भी 2.2 अरब डॉलर के स्विस बैंक खाते को चुनौती नहीं दी गयी थी।

सोनिया गांधी न तो मोरारजी देसाई की तरफ रिटायर्ड हैं न टायर्ड हैं। जब पहली बार उनके स्विस खाते के बारे में स्विस पत्रिका ने तथ्य छापे तब उनकी उम्र केवल 41 साल थी। वे आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और यूपीए की अध्यक्ष हैं। अगर यही खुलासा आडवाणी या मोदी के बारे में हुआ होता तो कल्पना कीजिये क्या होता? क्या मीडिया उसके तह तक नहीं जाता, क्या सरकार अब तक इस मामले में दोनों नेताओं को कठघरे में नहीं खड़ा करती।

यह मान लीजिये कि स्विस पत्रिका स्विट्जर इलस्ट्रैट और अलबेट्स की पुस्तक में गांधी परिवार के बारे में किये गये खुलासे गलत हैं तो इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हे खामोशी से यह सारे इल्जाम सह लेना चाहिए था? या एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते इस पर गंभीर प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी।

ईमानदारी मोरारजी देसाई ने दिखायी थी। 87 साल की उम्र में पुलित्जर पुरस्कार विजेता सीमोर हर्ष ने अपनी पुस्तक में उन पर यह आरोप लगाया था कि मोरारजी देसाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एजेंट थे और वे सीआईए से पैसे लेते थे। मोरारजी देसाई इस आरोप से तिल्ला गये और उन्होंने फौरन उसके खिलाफ 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मानहानि मुकदमा दायर कर दिये। मुकदमे की सुनवाई जब अंतिम स्थिति में पहुंची तब तक मोरारजी देसाई 93 साल के हो गये थे। वह अमेरिका जाने में असमर्थ थे।

किसिंजर, मोरारजी देसाई की तरफ से अदालत में पेश हुए और उन्होंने हर्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। अमेरिकी अदालत ने पाया कि हर्ष ने झूठे तथ्यों के आधार पर मोरारजी देसाई का नाम उछाला था और वह इस तरह के काम करने का आदी था। यह होती है ईमानदारी के लिये किसी भी हद तक जाना।

सोनिया गांधी न तो मोरारजी देसाई की तरफ रिटायर्ड हैं न टायर्ड हैं। जब पहली बार उनके स्विस खाते के बारे में स्विस पत्रिका ने तथ्य छापे तब उनकी उम्र केवल 41 साल थी। वे आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और यूपीए की अध्यक्ष हैं। अगर यही खुलासा आडवाणी या मोदी के बारे में हुआ होता तो कल्पना कीजिये क्या होता? क्या मीडिया उसके तह तक नहीं जाता, क्या सरकार अब तक इस मामले में दोनों नेताओं को कठघरे में नहीं खड़ा करती। ❑

स्वदेशी चर्म उद्योग के वाहक, श्रीलेदर्स के प्रतिष्ठाता

सुरेश चन्द्र दे

के जन्म शतवार्षिकी पर

स्वदेशी पत्रिका परिवार को हार्दिक शुभकामना

सुरेश चन्द्र दे

जन्म शतवार्षिकी

(1911–2010)

अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल

ईमानदार पर भ्रष्टाचार और महंगाई भारी

महंगाई के लिये न तो सरकार जिम्मेदारी ले रही है, न सरकार चलाने वाली कांग्रेस बल्कि कांग्रेस तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के उस कथन को जायज ठहराने में लगी है जिन्होंने पूरी दुनिया में महंगाई के लिये भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि भारतीय ज्यादा खाने लगे हैं अब इनके पास ज्यादा पैसे हो गये हैं।

■ विक्रम उपाध्याय

कभी प्याज तो कभी चीनी कभी गेहूं तो कभी तेल, ये है संप्रग सरकार के घोटाले के खेल। अब लगभग तीन साल होने को आये जबसे मंहगाई लगातार बढ़ रही है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में कितने सक्षम हैं, इस बात का अंदाज इससे ही लगाया जा सकता है कि अभी तक एक भी ऐसे उपाय नहीं हुए हैं जिससे जनता को मंहगाई से मुक्ति मिले। उल्टे सरकार की तरफ से ऐसी आपराधिक भूलें हुई हैं, जिससे जनता बेवजह मुनाफाखोरी की चक्की में पिसी है।

महंगाई के लिये न तो सरकार जिम्मेदारी ले रही है, न सरकार चलाने वाली कांग्रेस बल्कि कांग्रेस तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के उस कथन को जायज ठहराने में लगी है जिन्होंने पूरी दुनिया में महंगाई के लिये भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि भारतीय ज्यादा खाने लगे हैं अब इनके पास ज्यादा पैसे हो गये हैं। तब बुश के इस बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी।

ठीक इसी तरह का बयान कांग्रेस के बड़बोले महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी दिया। मध्यप्रदेश के अपने दौरे में कहा कि भारत में खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गयी है इसलिये महंगाई बढ़ रही है। यह उस सत्ताधारी पार्टी की अकर्मण्यता का परिचय है जो देश को आगे ले जाने और हर आम आदमी को खास बनाने का दावा करती है। शायद ही कोई ऐसा महीना बीतता हो जब यह सरकार किसी चीज की किल्लत बाजार में पैदा न करती हो। अभी प्याज की कीमत से निकलने वाले आंसू थमे ही नहीं कि चीनी को लेकर तमाम आशंकायें उत्पन्न हो गयी हैं। इसके पहले भी चीनी 50 रूपये किलो से ऊपर जा चुकी है। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और उसे लेकर सरकार में फुटबाल खेलने की नीति आखिर किसके इशारे पर चल रही है, यह जनता को जानना चाहिए।

क्या सरकार में शामिल कुछ मंत्री इसके लिये जिम्मेदार हैं? क्या कुछ खास व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये ऐसा किया जा रहा है? या फिर पूरी सरकार और उसको चलाने

शायद ही कोई ऐसा महीना बीतता हो जब यह सरकार किसी चीज की किल्लत बाजार में पैदा न करती हो। अभी प्याज की कीमत से निकलने वाले आंसू थमे ही नहीं कि चीनी को लेकर तमाम आशंकायें उत्पन्न हो गयी हैं। इसके पहले भी चीनी 50 रूपये किलो से ऊपर जा चुकी है। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और उसे लेकर सरकार में फुटबाल खेलने की नीति आखिर किसके इशारे पर चल रही है, यह जनता को जानना चाहिए।

वाली कांग्रेस पार्टी जनता की जेब पर डाका डालने के षड़यंत्र में शामिल है। अभी तक देखने में यह आया है कि अधिकतर कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के कुछ बड़े नेता चुपके से महंगाई की ठीकरा कृषि एवं खाद्यान्न मंत्री शरद पवार पर फोड़ डालते हैं। कांग्रेस बार–बार यह जताने की कोशिश करती है कि गठबंधन की मजबूरियों के कारण शरद पवार पर नकेल नहीं कसा जा सकता। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शरद पवार के मामले में बेचारे नजर आते हैं। शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से एक तरह से प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी कि वे चाहें तो कृषि एवं खाद्य मंत्रालय किसी और को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब भी खामोश रहे।

यह उनकी दयनीय स्थिति की द्योतक है या उनकी किसी मजबूरी की, यह वही बता सकते हैं। लेकिन जनता उनकी दयनीय स्थिति या मजबूरी की कीमत पूरी तरह से चुका रही है। अभी हाल ही में प्याज को लेकर खबर आयी थी कि प्रधानमंत्री ने मंत्री शरद पवार से कीमतों की वृद्धि की रिपोर्ट मांगी है। अगले ही दिन शरद पवार ने गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। मसला साफ है शरद पवार खुद को न तो जनता के प्रति जवाबदेही मानते हैं न प्रधानमंत्री के प्रति फिर भी सत्ता पर विराजमान हैं। उन्हें वे दो मंत्रालय प्राप्त हैं जिसके नकारेपन के कारण पूरे देश के किसान त्रस्त हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जनता को ढांढस बधाने के लिये ही सही, प्रधानमंत्री को ऐसा संदेश देना चाहिए कि सरकार मंहगाई के लिये जिम्मेदार लोगों पर लगाम कसने के लिये तैयार हैं। पर प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं रहे हैं। उनकी ईमानदारी की इमेज यहां धूमिल पड़ जाती है जब जनता त्राहि–त्राहि कर रही होती है।

अब सब लोगों ने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री की अक्रियशीलता जनता के प्रति संवेदनहीनता

और सरकार पर अनियत्रंण उनकी ईमानदारी पर हावी हो चुकी है। लोग उनकी ईमानदारी पर ही नहीं, उनकी क्षमता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।

अभी हाल ही में प्याज को लेकर खबर आयी थी कि प्रधानमंत्री ने मंत्री शरद पवार से कीमतों की वृद्धि की रिपोर्ट मांगी है। अगले ही दिन शरद पवार ने गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। मसला साफ है शरद पवार खुद को न तो जनता के प्रति जवाबदेही मानते हैं न प्रधानमंत्री के प्रति फिर भी सत्ता पर विराजमान हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहचान एक विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में है। उनकी तमाम उपलब्धियां भी अर्थ के क्षेत्र में ही है। ऐसे में जब देश आर्थिक रूप से ही विफल सिद्ध हो रहा हो तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। किसी के भी विफल होने के दो ही कारण हो सकते हैं या तो उसके अन्दर ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता की कमी है या उसके ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

प्रधानमंत्री के रूप में शायद दूसरी स्थिति से ही मनमोहन सिंह गुजर रहे हैं। योजनायें राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में बन रही हैं। उन पर क्रियान्वयन राजनैतिक लाभ और हानि की गणना के आधार पर हो रहा है। योजनाओं के लिये जिम्मेदार लोगों या नेताओं की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री के बजाय कांग्रेस नेतृत्व के प्रति है, आस्था प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सीमित है, भवि य लोग मनमोहन सिंह में नहीं कांग्रेस नेतृत्व में देख रहे हैं।

संभवतः इसलिये प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की कार्यकुशलता जमीन पर नहीं दिख रही है। ❑

भ्रष्टाचार और कीमतें सरकार की नहीं सुनती

तरह–तरह के घोटालों के आरोपों से घिरी यूपीए सरकार अब दिन–दिन बढ़ती महंगाई के मामले में भी फंसी हुई लग रही है। वादे–दर–वादे, आश्वासन–दर–आश्वासन के अलावा सरकार के पास कुछ रह नहीं गया है। वह हर बार सिर्फ आश्वासन दे देती है। पब्लिक हर बार की तरह बढ़े हुए भाव देखकर उन आश्वासनों की व्यर्थता पर सिर पीट सकती है। देश के जाने–माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, फिर भी महंगाई से निपटने का कोई रास्ता दिखायी नहीं पड़ रहा है। उस तबके की हालत लगातार खराब हुई है, जिसकी आय सीमित है या जिसकी आय महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती है।

■ आलोक पुराणिक

प्रधानमंत्री ने हाल में कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि मार्च 2011 तक महंगाई–दर गिरकर पांच दशमलव पांच प्रतिशत तक हो जाएगी। वैसे नवंबर 2010 का महंगाई का आंकड़ा 7.48 प्रतिशत रहा जो पिछले ग्यारह महीनों का न्यूनतम आंकड़ा है और वित्तमंत्री ने इस पर खुशी भी जाहिर की थी पर गौर से देखें, तो खाने–पीने की कई चीजों के भाव दो या तीन गुने से ऊपर चले गये हैं। यह आंकड़ा सचाई बयान नहीं करता।

मुक्त होती अर्थव्यवस्था में महंगाई जैसी दिक्कतें पेश आती हैं पर इसका निराकरण साप्ताहिक या पाक्षिक बयानों से नहीं होता। उसके लिए संस्थागत उपाय करने होते हैं। ताकि आर्थिक तौर पर विपन्न लोगों को राशन की दुकानों से सस्ता अनाज उपलब्ध हो। लेकिन उदारीकरण के शोरगुल में हमारे यहां सार्वजनिक वितरण–व्यवस्था यानी राशन की दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। इन दुकानों को चलाने में सिर्फ भ्रष्ट लोगों की दिलचस्पी है।

सरकार का यह कहना अब व्यर्थ सा लगने लगा है कि महंगाई बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी। कीमतें बहुत जल्दी कम हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने हाल में कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि मार्च 2011 तक महंगाई–दर गिरकर पांच दशमलव पांच प्रतिशत तक हो जाएगी। वैसे नवंबर 2010 का महंगाई का आंकड़ा 7.48 प्रतिशत रहा जो पिछले ग्यारह महीनों का न्यूनतम आंकड़ा है और वित्तमंत्री ने इस पर खुशी भी जाहिर की थी पर गौर से देखें, तो खाने–पीने की कई चीजों के भाव दो या तीन गुने से ऊपर चले गये हैं। यह आंकड़ा सचाई बयान नहीं करता।

वास्तविक महंगाई इस प्रतिशत से बहुत ऊपर है। खाने–पीने की चीजों में महंगाई का स्तर और भी ज्यादा है। प्याज इन दिनों साठ से सत्तर रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज के भाव सुनकर ही आंसू आ रहे हैं।

कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा बिल्कुल ही निरर्थक लग रहा है। तरह–तरह के घोटालों के आरोपों से घिरी सरकार अब दिन–दिन बढ़ती महंगाई के मामले में भी फंसी हुई लग रही है। वादे दर वादे, आश्वासन दर आश्वासन के अलावा सरकार के पास कुछ रह नहीं गया है। वह हर बार सिर्फ आश्वासन दे देती है। पब्लिक हर बार की तरह बढ़े हुए भाव देखकर उन आश्वासनों की व्यर्थता पर सिर पीट सकती है।

मौजूदा समय में जबकि देश के

संस्थागत उपाय इसलिए होते हैं कि आर्थिक तौर पर विपन्न लोग कीमतों की भयावहता महसूस न करें, उन्हें राशन की दुकानों से सस्ता अनाज उपलब्ध हो। लेकिन उदारीकरण के शोरगुल में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशन की दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। इनको चलाने में सिर्फ भ्रष्ट लोगों की दिलचस्पी है। राशन की दुकानों का सामान चोरी–छुपे खुले बाजार में पहुंच जाता है। ये सारी बातें राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार की जानकारी में भी हैं।

जाने–माने अर्थशास्त्री ही प्रधानमंत्री हैं, फिर भी महंगाई से निपटने का कोई रास्ता दिखायी नहीं पड़ रहा है। उस तबके की हालत लगातार खराब हुई है, जिसकी आय सीमित है या जिसकी आय महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती है।

सवाल है कि क्या मुक्त अर्थव्यवस्था इतनी मुक्त हो गयी है कि उस पर प्रधानमंत्री के आश्वासनों का भी कोई असर नहीं होता। इसका जवाब तो यही हो सकता है कि मुक्त अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार ऊपर जाने के लिए मुक्त हो गयी हैं। उन्हें नीचे लाने की सरकार की सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं।

हाल में शीतकालीन सत्र में भले ही संसद ने कुछ काम न किया हो, पर कीमतों की उछाल ने पूरा काम किया। पेट्रोल के भाव 2.95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े। 26 जून से यह पांचवी बढ़ोतरी है। पिछले पांच महीनों में पेट्रोल के भाव ही आठ रुपये बढ़ चुके हैं। खबर है कि डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव भी जल्दी ही बढ़ने वाले हैं।

पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उन तमाम वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिनकी लागत में परिवहन लागत शामिल होती है। अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं, जिनकी कुल लागत में परिवहन लागत शामिल ही होती है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है, जहां अभी कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। कीमतें ऊपर ही जा रही हैं, वे नीचे नहीं आ रही हैं, पर सरकार के आश्वासनों में कोई कमी नहीं है। कीमतें बढ़ने के साथ हर हफ्ते या पखवाड़े वह भी आ जाते हैं।

क्या कीमतें कम होने के आसार हैं? इस सवाल का जवाब है कि कीमतों पर अब आम तौर पर सरकार का कोई वश नहीं है। उनके ऊपर जाने, नीचे जाने की तमाम वजहों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हां, एक व्यवस्था यानी सस्ते दाम पर कई चीजें पब्लिक को मुहैया कराने में सरकार का वश था, यानी राशन की दुकान को ठीक ठाक चलवाना उसके बूते में था पर सस्ते राशन की दुकान भी अब एक ध्वस्त संस्थान है, भ्रष्ट संस्थान है। यह लगभग अप्रासंगिक हो चुका संस्थान है।

हाल में कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत आर्थिक प्रस्ताव में कहा गया है कि एक विकासशील देश में कुछ कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि उनकी आपूर्ति और मांग के

शीतकालीन सत्र में भले ही संसद ने कुछ काम न किया हो, पर कीमतों की उछाल ने पूरा काम किया। पेट्रोल के भाव 2.95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े। 26 जून से यह पांचवी बढ़ोतरी है। पिछले पांच महीनों में पेट्रोल के भाव ही आठ रुपये बढ़ चुके हैं।

लगातार ग्लोबल होती अर्थव्यवस्था में ग्लोबल कारक घरेलू कीमतों को प्रभावित करेंगे ही। उनके असर से बचा नहीं जा सकता। अगर कच्चे तेल के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हैं तो देर सबेर यहां भी महंगाई बढ़ेगी। उससे समाज के विपन्न तबके को कैसे बचाया जाये, यह सवाल महत्वपूर्ण है। पर इससे बड़ी विडम्बना यह है कि इस सवाल पर विचार करने की फुरसत किसी के पास नहीं है।

बीच असंतुलन होता है। कुछ कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि कई सेवाओं और वस्तुओं के निर्माताओं को ज्यादा कीमत दिये जाने की जरूरत होती है। कुछ कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं। कीमतें ऊपर जाने की वजहें तो आर्थिक प्रस्ताव में बता दी गयी है। पर मांग और आपूर्ति के सामान्य नियम ही अगर अर्थव्यवस्था को चलाएंगे तो फिर देश में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है।

प्याज का भाव अभी इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि इसकी आपूर्ति मांग के मुकाबले कमजोर है। गेहूं–आटे के भाव इस वजह से ऊपर गये हैं कि उनके उत्पादकों को ज्यादा कीमत दिये जाने की जरूरत थी। कच्चे तेल के भाव इसलिए बढ़ जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव ऊपर चले जाते हैं। अगर सब कुछ किसी ना किसी कारण पर ही निर्भर है, तो सवाल है कि सरकार किसलिए होती है।

महंगाई अगर तमाम आर्थिक कारकों का सहज परिणाम भर है, जिस पर सरकार का कोई वश या नियंत्रण नहीं है, तो सरकार का अर्थव्यवस्था में रोल क्या है। मुक्त होती अर्थव्यवस्था में ऐसी दिक्कतें पेश आती हैं। पर इन दिक्कतों के निराकरण साप्ताहिक या पाक्षिक बयानों से नहीं होते। उनके लिए संस्थागत उपाय करने होते हैं। यह संस्थागत उपाय इसलिए होते हैं कि आर्थिक तौर पर विपन्न लोग कीमतों की भयावहता महसूस न करें, उन्हें राशन की दुकानों से सस्ता अनाज उपलब्ध हो।

लेकिन उदारीकरण के शोरगुल में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशन की दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। इनको चलाने में सिर्फ भ्रष्ट लोगों की दिलचस्पी है। राशन की दुकानों का सामान चोरी–छुपे खुले बाजार में पहुंच जाता है। ये सारी बातें राज्य सरकारोंऔर केंद्रीय सरकार की जानकारी में भी हैं। पर इस स्थिति का निराकरण करने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति कहीं दिखायी नहीं पड़ती।

वामपंथी दल अपने लोकोन्मुख होने का बहुत शोर करते हैं पर पिछली बार उन्होंने सरकार से समर्थन इस मुद्दे पर वापस नहीं लिया कि राशन की दुकान को बेहतर बनाकर आम आदमी तक सस्ते अनाज की पहुंच बनायी जाये। सरकार से उनका समर्थन वापस हुआ परमाणु बिजली के मसले पर, जिसका आम आदमी से कम से कम अभी तक तो कोई लेना–देना नहीं है।

लेफ्ट की सरकार वाले पश्चिम बंगाल में राशन की दुकानों में विकट घोटाले हुए हैं। वामपंथी राशन की दुकानों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, ऐसे तथ्य सामने नहीं आते। लगातार ग्लोबल होती अर्थव्यवस्था में ग्लोबल कारक घरेलू कीमतों को प्रभावित करेंगे ही। उनके असर से बचा नहीं जा सकता। अगर कच्चे तेल के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हैं तो देर सबेर यहां भी महंगाई बढ़ेगी। उससे समाज के विपन्न तबके को कैसे बचाया जाये, यह सवाल महत्वपूर्ण है। पर इससे बड़ी विडम्बना यह है कि इस सवाल पर विचार करने की फुरसत किसी के पास नहीं है। ❑

गांधी जी का जंतर

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :– ''जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।''

– महात्मा गांधी

With Best Compliments from :

BHALOTIA MOTORS

(Authorised Mahindra Dealer)

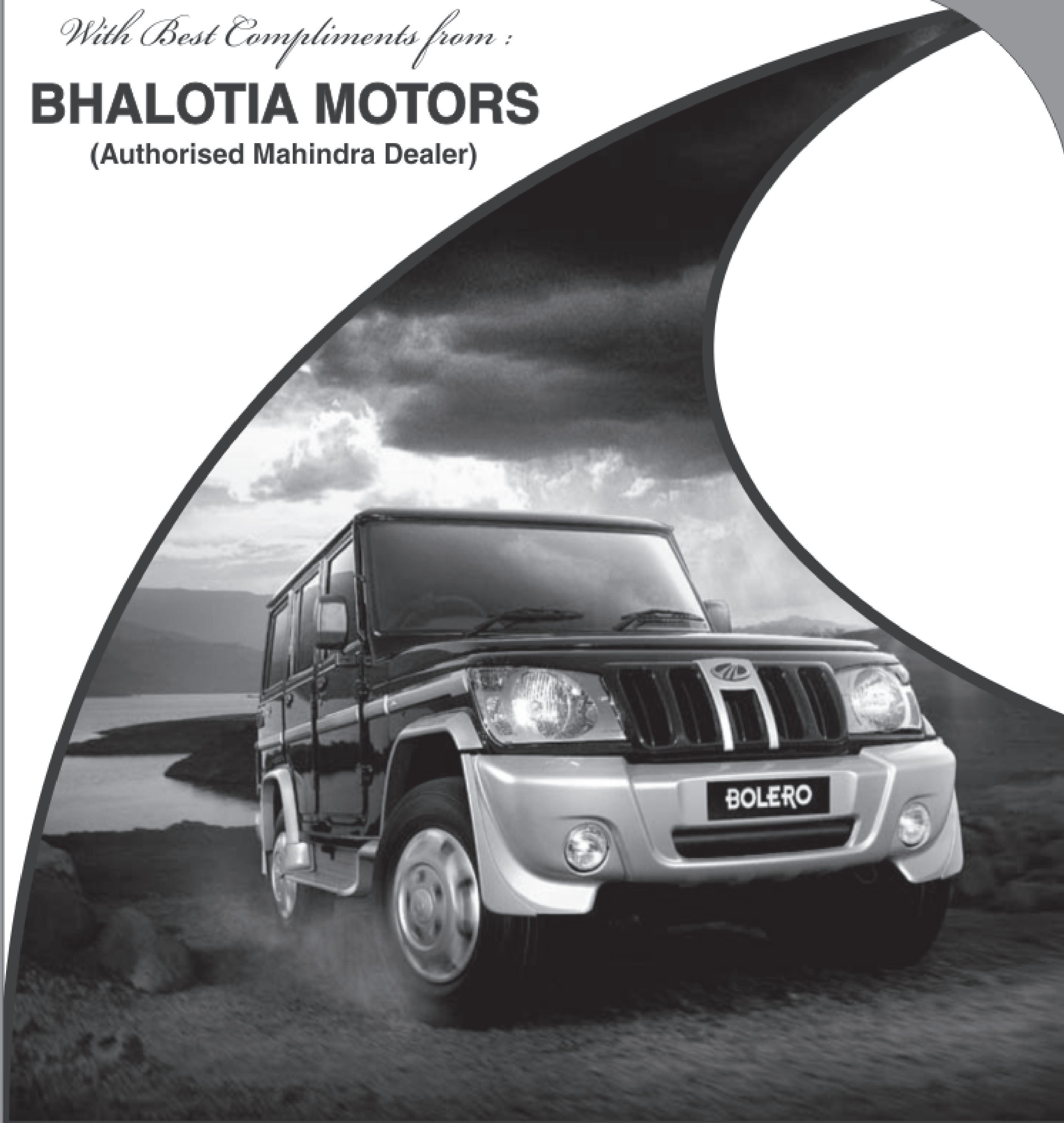

BHALOTIA MOTORS

(Sales & Service)

7th Phase, Industrial Area

Adityapur- Gamharia Main Road, Jamshedpur

Phone : 0657-2407497, 2408889

Mob. : 9234457153, 9234457154, 9234457157

E-Mail : bhl@teammahindramail.com / bhalotiajsr@sify.com

स्वदेशी जागरण मंच (बोकारो) द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन

झारखण्ड न सिर्फ खनिज सम्पदाओं से भरा पड़ा है बल्कि राष्ट्र के चिंतन करने वाले और राष्ट्रीय हित में काम करने वाले लोगों का भी कर्मस्थली रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसामुण्डा की तपोभूमि झारखण्ड स्वदेशी कार्यक्रमों के लिये भी एक आकर्षक जगह रही है। यहां समय–समय पर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम हुए हैं जिनसे राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा एवं दिशा मिली है। इस क्रम में सन् 2006 में जो कार्यक्रम हुआ था उसको याद करना लाजमी होगा।

स्वदेशी जारगण मंच (बोकारो) द्वारा 24 अगस्त 2006 को जैनामोड़ के गांगजोरी ग्राम में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में किसान महापंचायत में क्षेत्र के तमाम किसान समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में कृषि के विभिन्न प्रकार की विधियों की जानकारी दी गई। इस सम्मेलन की रिपोर्ट विभिन्न अखबारों द्वारा छपी गई। इसी खबर को हम (स्वदेशी पत्रिका झारखण्ड विशेषांक के रूप में) पाठकगणों के लिए यहां प्रस्तुत की जा रही है :–

गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि देश के 90 प्रतिशत लोगों की कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है। पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव ने जरीडीह प्रखंड अंतर्गत गांगजोरी ग्राम (बोकारो) में मंच द्वारा आयोजित विशाल किसान महासम्मेलन में सत्ता पक्ष को चेताते हुए कहा था कि विश्व में सर्वाधिक किसान भारत में हैं। पिछले 40–50 वर्षों से किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। जिस सरकार की जेब में 4 पैसा नहीं है और जो देश को 90 प्रतिशत रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में चवन्नी खर्च करने में दस बार सोचती है, वैसी सरकार किसके दम पर कहती है कि भारत को अमेरिका के साथ दंगल में उतारेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को प्रोत्साहन देने के बजाय अन्यायपूर्ण ढंग से विदेशों में गेहूं का आयात कर रही है और वालमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भारत में विक्रय केंद्र खोलने की दिशा में उदारता दिखा रही है। यह यहां के किसानों के स्वाभिमान पर कुठाराघात है।

उन्होंने पेप्सी कोला की बजाय छांछ और दूध का उपयोग करने जैसी छोटी

गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि देश के 90 प्रतिशत लोगों की कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है।

— *मुरलीधर राव*

बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की बात कही। सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यक्रम के संयोजक सेवानिवृत शिक्षक संतोष कुमार सम्मेलन में लगभग 4000 से 5000 किसान सम्मिलित हुए, जिनके बीच पोद्दार ट्रैक्टर्स की ओर से लक्की ड्रा किया गया। चार किसानों को महिन्द्रा ट्रैक्टर की चाबी श्री राव ने सौंपी।

सम्मेलन में भारतीय किसान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री श्री विनोद कुमार ने किसानों के सशक्तिकरण और जैविक खाद के प्रयोग पर जोर दिया।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. आर.के. ठाकुर और उदय कुमार ने बायो डीजल बनाने और उसके पौधे जेट्रोफा की खेती करने को प्रोत्साहित किया। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समुचित सहायता का आश्वासन दिया।

डॉ. सुधीर झा ने किसानों का मनोबल बढ़ाया। हजारी बाग के पूर्व सांसद सह मंच के प्रांतीय संयोजक महावीर लाल विश्वकर्मा ने किसानों को कहा कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की बजाय हम सभी को स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिनेश मंडल, बंदेशंकर सिंह, एस. बरियार, दीपक चौधरी, संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख अर्जुन सिंह, अरविंद त्रिपाठी, अमरेन्द्र कुमार ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन स्थल पर विज्ञान केंद्र, मोदी केयर के उत्पादों, टीवीएस के वाहनों और महिन्द्रा ट्रैक्टर्स की आकर्षक प्रदर्शनी लगयी गयी थी।❑

शिक्षा संस्कार एवं संस्तुति का सुन्दर समन्वय स्थल

सस्वती विद्या मन्दिर

भारत कोकिंग कोल लि0 (कोल इंडिया का एक अंग) के सहयोग से संचालित

भूली नगर, पोस्ट ऑफिस : श्रमिक नगर, धनबाद – 828105

(सरस्वती विद्या मन्दिर, भूली नगर, धनबाद, जिले का अग्रणी विद्यालय)

वरीय माध्यम विद्यालय / **Senior Secondary School**

संचालित : विद्या विकास समिति, झारखण्ड

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त

E-mail : svm_bhuli@fastermail.com Ph. 0326-2341620, 2340266

:: विद्यालय की विशेषताएं ::

- भव्य एवं विशाल विद्यालय भवन।
- आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला।
- अत्याधुनिक कम्प्युटर कक्ष।
- एल.सी.डी. के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।
- सुसज्जित बॉंट निकल गार्डेन।
- विशाल क्रीडा स्थल।
- सभी प्रमुख मार्गों से विद्यालय बस की व्यवस्था।
- भारत कोकिंग लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त।
- बी.सी.सी.एल. कर्मियों के पाल्य के लिए केवल 50 प्रतिशत मासिक शिक्षण शुल्क।
- विगत दस वर्षों से शत–प्रतिशत परीक्षा परिणाम।

निवेदक :

राजा राम शर्मा (प्राचार्य), विनय कुमार (सचिव), अनन्तनाथ सिंह (कोषाध्यक्ष)

TATA
TATA STEEL

For 100 years we've been part of the solution

When Tata Steel was set up as Asia's first integrated steel plant in 1907, it was with a commitment to invest in the betterment of society. For 100 years now, the credo of service has been a guiding light inspiring us to find new ways to improve the quality of life. Through initiatives in education, health care, rural development & income generation, population management, environment management and tribal welfare, we are planting smiles everyday.

It's part of our vision to become the global steel benchmark in value creation and corporate citizenship.

TATA STEEL
PRAGATI
Behtar Aaj Sunehra Kal

VERSUS '09

सस्वती विद्या मन्दिर

बागबेड़ा, जमशेदपुर (झारखण्ड)

नदी एवं पारिस्थितिकी

नदी भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की क्या, अपितु किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हम बिना सोचे–विचारे नदियों में कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ, मल–मूत्र, घरेलू अपमार्जक, भाव इत्यादि बहा देते हैं। परिणामस्वरूप पानी में संक्रामक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो जलीय जीव–जंतुओं सहित मानव शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है।

■ कौशल किशोर शर्मा

सौर प्रणाली में पृथ्वी ही एक मात्र नीला ग्रह है जहाँ जैविक सृष्टि का स्पंदन है। यह पृथ्वी जैविक सृष्टि हेतु पोशक तत्व जल, वायु तथा भूमि से सम्पन्न है। जल पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है जो कि जीवन के अस्तित्व का मौलिक आधार है, अर्थात् जल ही जीवन है।

अधिकांश देशों में मानवीय उपभोग तथा उपयोग के लिए जल का प्रमुख स्रोत नदियाँ और झीलों से भरा हुआ सतही मीठा जल है और भविष्य में यही जल काम आयेगा, परन्तु ये जल भंडार असीम जलराशि से कहीं कम है।

नवीनतम आँकड़ो के अनुसार नदियाँ और झीलों में 25,000 घन कि.मी. से अधिक जल नहीं है। पृथ्वी पर कुल वार्षिक वृष्टिपात 1,19,000 घन कि.मी. है, परंतु इस जल राशि का 45,000 घन कि. मी. जल आर्कटिक और अंटाकर्टिक हिमनदों द्वारा समुद्र में जाता है। शेष जल वाष्पीकृत होकर वायुमण्डल में उड़ जाता है एवं पृथ्वी में छन कर लगभग 30 प्रतिशत मीठा जल गहराई तक पहुँच जाता है। इस प्रकार वार्षिक वृष्टिपात से नदियों का जल – प्रवाह बना रहता है।

नदियों के रूप में सतही–जल लगभग 93,100 घन कि.मी. प्रवाहित होता है, जो कि कुल पानी का मात्र एक प्रतिशत होता है, जो कि कुल पानी का मात्र एक प्रतिशत है। अतः नदियाँ ही मुख्यतया मीठा सतही जल के रूप में मनुष्य एवं पशु–पक्षी के लिए उपलब्ध है।

मनुष्य को अपने दैनिक उपयोग हेतु कितना स्वच्छ जल चाहिए, इसका अनुमान कुछ दिये गये उदाहरणों से लगाया जा सकता है – एक टन कागज के निर्माण में 50 हजार गैलन, एक टन इस्पात बनाने में 25 हजार गैलन, एक लीटर पेट्रोल तैयार करने में 10 लीटर, एक टन सीमेंट तैयार करने में 3.5 हजार लीटर तथा एक टन एसीटेट बनाने में 2 लाख 50 हजार गैलन पानी चाहिए। खाने–पीने, कपड़े धोने आदि में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 80 लीटर स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। घरेलू उपयोग में एक आदमी 60 हजार लीटर जल हर वर्ष व्यय करता है, जोकि हमारे कुल उपयोग का 40 प्रतिशत है।

भारतवर्ष में नदियों का जितना गुणगान किया गया है शायद ही किसी और देश की भाषा में हो। वेदों की सारी प्रार्थनाओं में पानी से नदियां संपन्न हो, भरपूर वर्षा हो यह बार–बार कहा गया है। हमारे शिवपुराण में जल स्त्रोंतों की रक्षा करने वाला भी मोक्ष का अधिकारी होता है ऐसा कहा गया हैः

''पानी दानं परमम्, दानानाम् उत्तम तदा।
सर्वेशां जीव पुंजानाम्, तर्पणम् जीवनम् स्मृतम्।।''

यहां जलाशय संपत्ति, संस्कृति, सत्ता और सेवा का प्रतीक है। हमारी अधिकांश मुख्य नदियां, जैसे गंगा, यमुना,

गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र आदि जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है।

विश्व के कुछ देशों में और उनके अंशभूत क्षेत्रों में स्वच्छ एवं ताजे जल का अभाव है और यह अभाव जनसंख्या की वृद्धि, उद्योग और कृषि के विकास के कारण निरंतर बढ़ता जाता है, फलस्वरूप पशुओं तथा वनस्पतियों के प्रयुक्त दूषित जल से उनकी अपूरणीय क्षति होती है तथा जीवमंडल संबंधी परिस्थिति विज्ञान का संतुलन बिगड़ जाता है।

दुनिया भर के उद्योग लगभग 160 घन कि.मी. जल हर वर्ष प्रदूषित करते हैं। हमारी नदियां भी इन समस्याओं से आक्रांत होती जा रही है। इन आद्रभूमि वर्ग में नदियाँ, झीलें, दलदली क्षेत्र, जल–जमाव का क्षेत्र या इनके तरह के क्षेत्र विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वास स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। आज आद्रभूमि संसार में सबसे ज्यादा पारिस्थितिकीयों में से एक है। इनके गुणतत्वों में निरंतर कमी हो रही है, इससे जल से संबंधित समस्या और भी जटिल होती जा रही है। जलीय जैवविविधता एवं उसके प्राकृतिक वास में कमी मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे हैं।

स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन या अस्तित्व की क्या, किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हमें मानव सभ्यता को जल प्रदूषण के खतरों से बचाना है तो नदियों को प्रदूषित होने से रोकना नितांत आवश्यक है। अन्यथा जल प्रदूषण से होन वाले खतरे मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जायेंगे। समस्या समाधान हेतु हमें नदियों की सूची मानचित्रण व संरक्षण योजना हेतु एक दीर्घकालीन एकीकृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में गंगा नदी के 60 कि.मी. विस्तार, सुल्तानगंज से कहलगांव तक, का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी के जलीय तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रलेखीकरण तथा इन कारकों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। अध्ययन क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का चित्रांकन करना तथा उसके फैलाव संबंधित परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना। गंगा नदी संपोषित सामान्य जैव–रूप का अध्ययन कर उसके महत्व एवं अस्तित्व के संदर्भ में स्थानीय जलीय आहार–जाल के तुलनात्मक विवरण का विश्लेषण करना। पक्षियों के संदर्भ में यह प्रलेखीकरण करना है कि इस नदी का उपयोग किस प्रजाति के पक्षी कर रहे हैं तथा वर्ष के किस मौसम में यह परिवर्तन हो रहा है। पक्षियों की संख्या में यह मौसमी बदलाव किस खास क्षेत्र विशेष में हा रहा है उसका भी आकलन करना।

अनुवर्ती क्रियाशीलन के अंतर्गत स्थानीय नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना भी इस अध्ययन का उद्देश्य है ताकि उनके क्रिया–कलाप के व्यवधान में कमी हो और नदी के महत्व को वे समझें। स्थानीय नदी विस्तार की सुरक्षा हेतु वहां के प्रशासन से संपर्क कर समस्याओं की जानकारी दें तथा समय अंतराल में अनुश्रवण कर गंगा नदी को स्वच्छ एवं सुरक्षित रख सकते हैं तभी हम सही अर्थ में सबका विकास, सब में विकास और सब के लिए विकास कर सकते हैं।

गंगा नदी के लिए अपने यहां मातृत्व की श्रद्धा है। गंगा के प्रति यह अप्रतिम श्रद्धा तथा कुंभ मेला का अलौकिक दृश्य वर्णनातीत है। यहां की छोटी–मोटी नदियां भी हमारे लिए पवित्र हैं। हर दिन स्नान करते समय श्रद्धालु 'गंगेच यमुने चैव.....' मंत्र उच्चारण करते समय समस्त भूमि की पवित्रता की आव्हान करता है। हमारे यहां नदी की पूजा की जाती है। उसे गंदा करना दोश माना जाता है। हममें 'पुण्य क्षेय' सभी नदी के किनारे होते हैं।

प्यासे को पानी पिलाना हमारी उत्कृष्ट परंपरा रही है। अतः जल–स्रोत साफ सुथरा रहे, यह विचार होता रहा है। परन्तु, आज का विकास पूर्णतया भोगवाद की संस्कृति पर आधारित होने के कारण हमारी सुरचित सांस्कृतिक, सामाजिक रचनाओं की, व्यवस्थाओं की एवं मूल्यों की जड़ें नष्ट होने लगी हैं। विस्तारित औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण की दौड़ में हम अपना जीवन शैली, सोच एवं विकास में परिवर्तन लाये हैं, जिसके फलस्वरूप जल–स्रोंतों पर विघातक प्रभाव पड़ता है।

नदी भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की क्या, अपितु किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हम बिना सोचे–विचारे नदियों में कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ, मल–मूत्र, घरेलू अपमार्जक, भाव इत्यादि बहा देते हैं। परिणामस्वरूप पानी में संक्रामक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो जलीय जीव–जंतुओं सहित मानव शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। लगभग 70 प्रतिशत संक्रामक बिमारियां, जैसे पीलिया, हैजा, पेचिस, क्षय, आदि जल संबंधित हैं। दूषित जल के साथ–साथ ही फीताकृमि, गोलकृमि, आदि मानव में प्रविष्ट करते हैं जिससे व्यक्ति विशेष रोगग्रस्त होता है। जल में कारखानों के मिलने वाले अवशिष्ट

पदार्थ तथा उसके गर्म जल, कीटनाशक तत्व, इत्यादि नदी के जल को दूषित करने के अलावा वहां के वातावरण को भी गर्म करते हैं जिससे जलीय वनस्पति व जंतु प्लावकों की संख्या में कमी के साथ–साथ जलीय पर्यावरण को असंतुलित करने में सहायक होते हैं।

उत्तर भारत की छह पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोमती एवं सरयू है।

दक्षिण भारत की छह पवित्र नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी है।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा भारत में नदियों की स्थिति पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 11–12 दिसंबर 2010 को जमशेदपुर में हुआ। भारत में नदियों की स्थिति दिनोंदिन बद–से–बदतर होती जा रही है। अनेक नदियों पर तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। औद्योगिक विकास की रीढ़ नदियां ही रही है परंतु आज उन्हीं उद्योगों से निकलने वाले कचड़े और रसायन नदियों को प्रदूषित कर रही है। प्राचीन काल से पूरे दुनिया में नगेरा का विकास किसी न किसी नदी तट पर हुआ है। परंतु अतिक्रमण के कारण शहरों में अनेक नदियां सिकुड़ती जा रही है और नागरीय कचड़े नदी को समाप्त करने पर तुले हैं। कहीं बांध के कारण नदियों की स्थिति खराब हो रही है।

उपरोक्त विषयों पर अनेक लोग देश के विभिन्न हिस्सों में नदियों पर कार्य कर रहे हैं। परन्तु एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय सोच इन विषयों पर नहीं बन पाया है। अपने क्षेत्र के नदियों की समस्याओं के अनुरूप लोग आंदोलन अथवा जागरण का कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं पर एक सामूहिक सोच विकसित हो इसके लिए एक सार्थक पहल करते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसमें वर्तमान विकास मॉडल के कारण नदियों पर उत्पन्न खतरे, अक्षय नदी व्यवस्था एवं विकास, नदियों का अर्थशास्त्र से लेकर नदी एवं पारिस्थितिकी आदि अनेक बिंदुओं पर विभिन्न सत्रों में चर्चा होगी। इस सेमिनार में देशभर से लगभग 150 प्रतिनिधि भाग लिया।

(लेखक पी.जी. जंतुविज्ञान विभाग कोपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर में कार्यरत हैं।)

पूज्य तपस्वी जगजीवन जी महाराज

सरस्वती विद्या मंदिर

जनवृत–3/सी, बोकारो इस्पात नगर
विद्या विकास समिति (झारखण्ड), राँची से सम्बद्ध
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त
मान्यता क्रमांक – 3430022, विद्यालय संख्या – 08013
दूरभाष : 06542-247579, 223055 (P&T), 88285 (Max), E-Mail : bsc_ptjm@bsnl.in

:: विशेषताएँ ::

● शत–प्रतिशत परीक्षाफल ● नगर एवं उपनगरों के विभिन्न मार्गों से बस सुविधा ● अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय ● कुशल एवं निपुण आचार्यों द्वारा अध्यापन ● प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में विशाल भवन युक्त स्थान ● क्रीड़ा एवं शैक्षणिक उपलब्धियों में सदैव अग्रसर ● मेधावी सह–निर्धन छात्रों हेतु निःशुल्क अध्यापन व्यवस्था ● समय–समय पर सभी विषयों पर कार्यशालायों का आयोजन ● अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त शिशु प्रवेश से लेकर पंचम तक की अध्यापन व्यवस्था ● उपेक्षित बस्तियों में संस्कार केन्द्रों का संचालन ● प्रति वर्ष चिकित्सा, प्रबंधन व तकनीकी संस्थानों में दर्जनों भैया–बहन का नामांकन ● संस्कारक्षम वातावरण में अनुशासन व भारतीय संस्कृति से भैया–बहनों का लगाव ● स्वावलंबी तथा समाजसेवी की भूमिका में आगे बढ़ने की प्रेरणा।

श्री परमेश्वर लाल वर्णवाल
सचिव

श्री सुभाष नेत्रगाँवकर
अध्यक्ष

श्री शिव कुमार सिंह
प्राचार्य

रपट

नदियां ही नहीं बचेंगी तो मानव अस्तित्व भी नहीं बचेगा

आज भारत में नदियों के सूखने, जल प्रदूषण व अतिक्रमण का कारण बिना विचार हो रहा विकास है। विकास की जिस पैशाचिक परिकल्पना पर भारत सरकार चल रही है, वह न केवल नदियों बल्कि मानव अस्तित्व को खत्म कर देंगी।

– अरुण ओझा

स्वदेशी जागरण मंच (जमशेपुर) द्वारा बीते वर्ष 11–12 दिसंबर 2010 को दो दिवसीय सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय था भारत में नदियों की स्थिति।

इसमें वक्ताओं ने नदियों की दुर्दशा के लिए विकास के वर्तमान मॉडल को जिम्मेदार ठहराया।

आज विकास के नाम पर नदियों का अविरल प्रवाह रोका जा रहा है, इससे उनका अस्तित्व खतरे में है। यदि नदियां ही नहीं बचेंगी तो मानव अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में नदियों को बचाना होगा।

मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा ने कहा कि आज भारत में नदियों के सूखने, जल प्रदूषण व अतिक्रमण का कारण बिना विचार हो रहा विकास है। विकास की जिस पैशाचिक परिकल्पना पर भारत सरकार चल रही है, वह न केवल नदियों बल्कि मानव अस्तित्व को खत्म कर देंगी।

स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली के डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि नदियों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार है। आज विकास का जो पश्चिमी मॉडल भारत में अपनाया जा रहा है वह नदियों के आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और आर्थिक पक्ष को नकारता है। वर्तमान समय में सरकारी नीतियां के करण ही नदियां आज प्रदूषित हो रही हैं।

झारखंड सरकार के खनन एवं भूगर्भ विभाग के पदाधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि नदियों का यदि कुशल प्रबंधन न हुआ तो उनका अस्तित्व बचना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि नदियों को बचाने के लिए कुशल प्रबंध तंत्र विकसित करने की जरूरत है। तभी नदियों का अविरल प्रवाह सुनिश्चित होगा और उन्हें प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा।

सेमिनार में झारखंड सरकार के खनन एवं भूगर्भ विभाग के पदाधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि नदियों का यदि कुशल प्रबंधन न हुआ तो उनका अस्तित्व बचना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि नदियों को बचाने के लिए कुशल प्रबंध तंत्र विकसित करने की जरूरत है। तभी नदियों का अविरल प्रवाह सुनिश्चित होगा और उन्हें प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा।

सेमिनार में भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के गांधी दर्शन एवं विचार विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने कहा कि नदिया मानव जीवन की पोषक है। यदि नदियों को बचाने के कारगर प्रयास न हुए तो मानव जीवन निश्चित ही प्रभावित होगा।

नई दिल्ली जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हेमंत ध्यानी ने विकास के वर्तमान मॉडल को नदियों के लिए खरतनाक बताया। साथ ही सुझाव दिया कि नदियों की स्थिति सुधारने के लिए विकास के वर्तमान मॉडल का विश्लेषण और आवश्यकतानुसार उसमें बदलाव जरूरी है।

इसके अलावा वक्ताओं ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि आने वाले समय में पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी आवश्यकता और भौगोलिक संरचना को दृष्टि में रखते हुए नदियों के जल का प्रबंधन करना होगा। ❑

जल स्रोतों को रखो साफ, प्रदूषण घटेगा अपने आप।
मत करो जल की बर्बादी, किसने दी इसकी आजादी।
नदी बचाओ–जल बचाओ, जीवन का आदर्श बनाओ।

परंपरागत ज्ञान से ही होगा किसान का विकास

सुभाष के अनुसार, 1988 से 1994 के बीच का समय मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी का समय था। तब मैंने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उपाय ढूंढा और कर्ज का जुआ उतार फेंका। मैंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कृषि पद्धति को तिलांजलि दे दी और आर्गेनिक कृषि को अपना लिया। इससे एक नई शुरुआत हुई। वह कहते हैं कि कर्ज के इस भयावह चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि किसान हरित क्रांति के कृषि मॉडल का त्याग कर दें। हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में मूलभूत खामियां हैं। इसमें कभी भी किसान के हाथ में पैसा नहीं टिक सकता।

■ देविंदर शर्मा

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों के खूनखराबे के लिए सबसे अधिक दोषी कृषि अधिकारी और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। रोजाना दर्जनों किसान रासायनिक कीटनाशक पीकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर लेते हैं। पिछले 15 वर्षों में कृषि विनाश का बोझ ढोने में असमर्थ दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है।

2010 तो इतिहास बनने जा रहा है। मैं सशंकित हूं कि क्या नया साल किसानों के लिए कोई उम्मीद जगाएगा? अनेक वर्षों से मैं नए साल से पहले प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह साल तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ। साल दर साल किसानों की आर्थिक दशा बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही कृषि भूमि किसानों के लिए अलाभकारी होकर उनकी मुसीबतें बढ़ा रही है। रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी जहरीली हो रही है। अनुदानित हाइब्रिड फसलें मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर रही हैं और भूजल स्तर को गटक रही हैं।

इसके अलावा इन फसलों में बहुतायत से इस्तेमाल होने वाले रासायनिक कीटनाशक न केवल भोजन को विषाक्त बना रहे हैं, बल्कि और अधिक कीटों को पनपने का मौका भी दे रहे हैं। परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी घटने से वे संकट में फंस रहे हैं। खाद, कीटनाशक और बीज उद्योग किसानों की जेब से पैसा निकाल रहा है, जिसके कारण किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों के खूनखराबे के लिए सबसे अधिक दोषी कृषि अधिकारी और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। रोजाना दर्जनों किसान रासायनिक कीटनाशक पीकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर लेते हैं।

पिछले 15 वर्षों में कृषि विनाश का बोझ ढोने में असमर्थ दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह सिलसिला रुकता दिखाई नहीं देता। पुरजोर प्रयासों के बावजूद करोड़ों किसान अपनी पीढ़ियों को विरासत में कर्ज देने को मजबूर हैं।

सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों

को अकारण दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, किंतु एक हद तक किसान भी इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का लोभ उन्हें गैरजरूरी प्रौद्योगिकियों की ओर खींच रहा है, जो अंततः उनके हितों के खिलाफ हैं। लंबे समय से किसान उपयोगी कृषि व्यवहार से विमुख होते जा रहे हैं और कृषि उद्योग व्यापार के जाल में फंसते जा रहे हैं।

उद्योग उन्हें एक सपना बेच रहा है – जितनी अधिक उपज प्राप्त करोगे, उतनी ही कमाई होगी, जबकि असलियत में उद्योग जगत का मुनाफा बढ़ रहा है, किसानों को तो मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हरित क्रांति के 40 साल बाद 90 प्रतिशत से अधिक किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

मानें या न मानें, देश भर में किसान परिवार की औसत आय 2400 रुपये से भी कम है। यह भी तब जब किसान अधिक आय के चक्कर में तमाम प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक रूपों में किसानों के साथ जो श्राप जुड़ गया है उसके लिए वे भी कम जिम्मेदार नहीं हैं।

जरा इस पर विचार करें कि क्या किसानों को कृषि संकट के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? आप कब तक सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों के सिर ठीकरा फोड़ते रहेंगे। आप कृषि से दीर्घकालिक और टिकाऊ तौर पर अधिक आय हासिल क्यों नहीं करते?

कृपया यह न कहें कि यह असंभव है। अगर किसान अपने परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल कृषि में करें तो वे इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के यवतमल जिले के डरोली गांव के सुभाष शर्मा से मिलिए। वह उस विदर्भ पट्टी से हैं जहां बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन वह कृषि से अच्छी–खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं। सुभाष शर्मा कोई बड़े किसान नहीं हैं। उनके पास 16 एकड़ जमीन है। देश में अधिकांश किसानों की तरह वह भी कर्ज के जाल में फंसे हुए थे।

सुभाष के अनुसार, 1988 से 1994 के बीच का समय मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी का समय था। तब मैंने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उपाय ढूंढा और कर्ज का जुआ उतार फेंका। मैंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कृषि पद्धति को तिलांजलि दे दी और आर्गेनिक कृषि को अपना लिया। इससे एक नई शुरुआत हुई। वह कहते हैं कि कर्ज के इस भयावह चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि किसान हरित क्रांति के कृषि मॉडल का त्याग कर दें। हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में मूलभूत खामियां हैं। इसमें कभी भी किसान के हाथ में पैसा नहीं टिक सकता।

मानें या न मानें, देश भर में किसान परिवार की औसत आय 2400 रुपये से भी कम है। यह भी तब जब किसान अधिक आय के चक्कर में तमाम प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक रूपों में किसानों के साथ जो श्राप जुड़ गया है उसके लिए वे भी कम जिम्मेदार नहीं हैं।

अब वह देश भर में कार्यशाला आयोजित कर किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि के तरीकों से कर्ज के जाल को कैसे काटा जा सकता है। कृषि संवृद्धि और देश की खाद्यान्न सुरक्षा का जवाब इसी में निहित है।

सुभाष शर्मा की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है कि उन्होंने कामगारों के लिए 15 लाख का आपात कोष भी जुटा लिया है। किसी की मृत्यु होने पर या फिर बेटी के विवाह के अवसर

पर उनके सामाजिक सुरक्षा कोष से कुछ राहत मिल जाती है। वह श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाते हैं। इसके अलावा उन्हें बोनस और छुट्टी यात्रा का भत्ता भी देते हैं।

चौंकिए मत, सुभाष शर्मा अपने 51 कामगारों को प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये का बोनस देते हैं, जो प्रति व्यक्ति 9000 रुपये बैठता है। वह अपने श्रमिकों को साल में एक बार घूमने के लिए छुट्टी देते हैं। प्रत्येक कामगार को साल में पचास दिन की छुट्टियां मिलती हैं। एक ऐसे समय में जब शायद ही किसी दिन श्रमिकों के साथ अमानवीय अत्याचार की खबरें न आती हों, इस तरह का रवैया सुखद आश्चर्य में डालने वाला है।

चौंकिए मत, सुभाष शर्मा अपने 51 कामगारों को प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये का बोनस देते हैं, जो प्रति व्यक्ति 9000 रुपये बैठता है। वह अपने श्रमिकों को साल में एक बार घूमने के लिए छुट्टी देते हैं। प्रत्येक कामगार को साल में पचास दिन की छुट्टियां मिलती हैं। एक ऐसे समय में जब शायद ही किसी दिन श्रमिकों के साथ अमानवीय अत्याचार की खबरें न आती हों, इस तरह का रवैया सुखद आश्चर्य में डालने वाला है।

जहां तक कीटनाशकों का सवाल है, हरियाणा के जींद जिले में चुपचाप एक क्रांति हो रही है। यहां के किसान बीटी कॉटन पैदा नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक परभक्षियों पर भरोसा करते हैं। ये परभक्षी कीट नुकसानदायक कीटों को चट कर जाते हैं। उन्होंने कपास में लगने वाले प्रमुख कीट मिली बग का प्राकृतिक उपाय खोज निकाला है।

जींद के सुरेंद्र दलाल ने बड़े परिश्रम के बाद मिली बग को काबू में करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने इस विषय पर काफी शोध किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि नुकसान न पहुंचाने वाली आकर्षक लेडी बीटल इन मिली बगों को चट करने के लिए काफी हैं। यह इन मिली बग को बड़े चाव से खाती है, जिससे किसानों का महंगे कीटनाशकों पर पैसा खर्च नहीं होता।

उन्होंने महिला पाठशाला भी शुरू की है। इन दो किसानों ने कृषि क्षेत्र में नया अध्याय लिख दिया है। अब सही समय है कि आप इनकी सफलता से सबक लें और कृषि का खोया हुआ गौरव वापस लौटा दें। निश्चित तौर पर आप यह कर सकते हैं। इसके लिए बस दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों के लिए नया वर्ष नया हर्ष लेकर आएगा। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

नीतिश ने दिखायी नयी राह

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक निधि को खत्म करके और भ्रष्ट अधिकारियों की सम्पत्ति की जब्ती कानून बनाकर बिहार और देश को नई राह दिखायी है। इससे बिहार को ही नहीं बल्कि देश को नयी दिशा मिलेगी।

■ निरंकार सिंह

यदि नेता ईमानदार और दूरदृष्टि वाला हो तो कोई भी कार्य असंभव नही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक निधि को खत्म करके और भ्रष्ट अधिकारियों की सम्पत्ति की जब्ती कानून बनाकर बिहार और देश को नई राह दिखायी है। इससे बिहार को ही नहीं बल्कि देश को नयी दिशा मिलेगी। बिहार सरकार सेवा का अधिकार कानून बनाने का फैसला पहले ही कर चुकी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी विभागों में एक तय अवधि के भीतर लोगों के काम हो जायें।

यह सेवा कानून भी नीतीश सरकार का ऐसा फैसला है जिससे दूसरे राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। देश के राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को विधायक निधि के नाम पर अलग अलग राज्यों में तीन करोड़ से लेकर पच्चीस लाख रूपये तक मिलते हैं। उनकी सिफारिश पर स्थानीय स्तर पर विकास कार्य कराये जाते हैं। लेकिन कई विधायकों द्वारा मनमाने तरीके इस धनराशि के खर्च करने और उसमें से कमीशन लेने के कारण आम विधायकों की छवि भी जनता में खराब हुई है। इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और विधायकों के सम्मान को बनाए रखने के इरादे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक निधि की व्यवस्था समाप्त कर दी है।

उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने को जिले के अभिभावक और स्थानीय विधायक की भांति देखें और योजनाओं की निगरानी करें।

आज हमारी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार ही है। कोई योजना और कार्यक्रम ऐसा नही जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। लेकिन भ्रष्टाचार अब पतन की उस पराकाष्ठा पर पहुँच गया है जो देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा बन गया है। 2–जी स्पेट्रम और राष्ट्र मण्डल खेलों में जैसे घोटाले हुए हैं। वे साधारण घोटाले नही है बल्कि इस राष्ट्र के साथ अपराध और धोखा धड़ी है।

ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने विधायक निधि को खत्म करने का फैसला करके एक सराहनीय काम किया हैं। यह एक साहसिक कदम है क्योंकि कई दलों के सांसद और विधायक इन निधियों के बढ़ाने की लगातार मांग करते रहे हैं।

आज हमारी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार ही है। कोई योजना और कार्यक्रम ऐसा नही जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। लेकिन भ्रष्टाचार अब पतन की उस पराकाष्ठा पर पहुँच गया है जो देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा बन गया है।

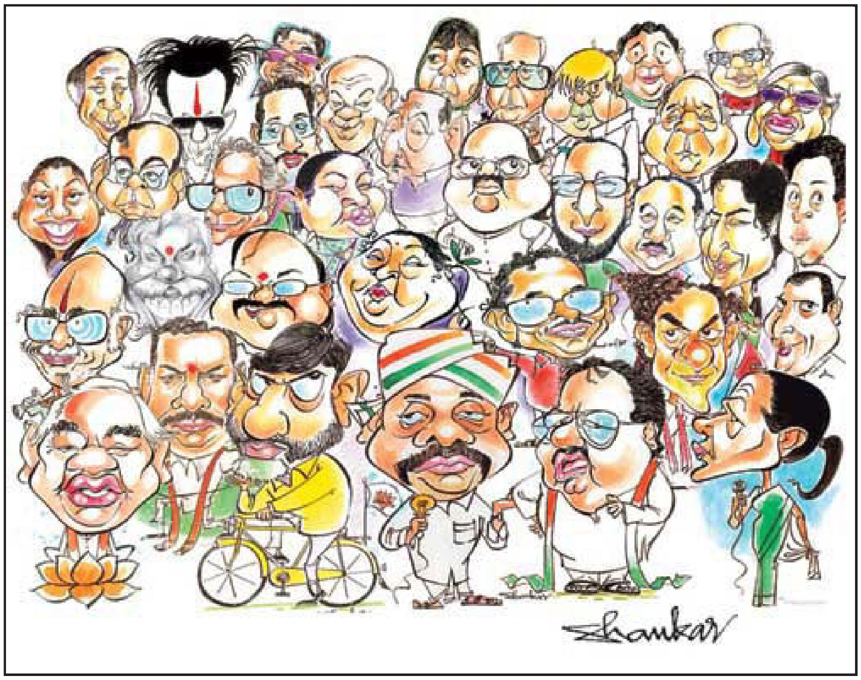

पिछले कुछ वर्षो में इस देश की राजनीति के नैतिक पतन के लिए यदि कोई एक कारण सर्वाधिक जिम्मेदार साबित हुआ है तो वह सांसद–विधायक क्षेत्र विकास निधि है। कुछ थोड़े से सांसद या विधायक इस फंड से कमीशन से न भी लेते हों पर दुरूपयोग के आरोप इतने है कि इसे लेकर आम जनता में आम सांसदों व विधायकों की इज्जत घटी है।

लेकिन अब यह कोई छिपी बात नहीं है कि अधिसंख्य सांसद और विधायक इस मद में दी गयी धनराशि का 40 से 50 फीसदी भाग कमीशन के रूप में खुद हड़प कर जाते हैं।

कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल ने खुफिया कैमरे से कुछ सांसदों के इस गोरख धंधे को उजागर किया था। जिन सांसदों और विधायकों को लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी का काम करना चाहिए था उनमें से कई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ठेकेदारी का धंधा करने लगे।

कुछ दिन पहले ही बिहार में सांसद निधि में कमीशन को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या हो गयी थी। इसलिए नीतीश कुमार ने विधायक निधि को खत्म करके यूपीए सरकार और अन्य राज्यों को नयी राह दिखायी है कि जनप्रतिनिधियों का जीवन और आचरण जनता के लिए प्रेरक होना चाहिए। विधायक निधि यदि राजनीति में नैतिक गिरावट का कारण बन जाए तो खत्म कर देना ही बेहतर है।

पिछले कुछ वर्षो में इस देश की राजनीति के नैतिक पतन के लिए यदि कोई एक कारण सर्वाधिक जिम्मेदार साबित हुआ है तो वह सांसद–विधायक क्षेत्र विकास निधि है। कुछ थोड़े से सांसद या विधायक इस फंड से कमीशन से न भी लेते हों पर दुरूपयोग के आरोप इतने है कि इसे लेकर आम जनता में आम सांसदों व विधायकों की इज्जत घटी है। इसके भ्रष्टाचार के कारण ब्यूरोक्रेसी पर से सांसदों और विधायकों की नैतिक धाक भी समाप्त हो रही है। इस निधि के पैसों में से कमीशन लेने वाले सांसदों और विधायकों मे यह नैतिक साहस कहां बचेगा कि वे सरकार की ओर से चलाये जा रहे दूसरे विकास और कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके? सांसद फंड की शुरूआत से पहले आम जनता अपने सांसदों–विधायकों से यह उम्मीद करती थी कि जरूरत पड़ने पर किसी प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सांसद–विधायक की मदद ली जा सकती है। पर जब खुद अधिकतर सांसदों और विधायकों द्वारा ही सम्बंधित अधिकतर अफसरों से सांठ–गांठ करके इस फंड के दुरूपयोग की खबरें आने लगीं तो आम लोगों में नेताओं और लोकतंत्र के प्रति आस्था कम होने लगी जिसकी आशंका करीब आठ साल पहले मन मोहन सिंह ने राज्य सभा में व्यक्त की थी। लेकिन मनमोहन सिंह जिस सांसद निधि को खत्म करने का साहस नहीं कर सके उसे बिहार में विधायक निधि को खत्म करके नीतीश कुमार ने दिखा दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी अपने कार्यकाल में सभी प्रमुख दलों के नेताओं से बात करके सांसद निधि के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की जरूरत पर जोर दिया था। सैद्धांतिक रूप से उनसे सहमति जताने के बावजूद किसी भी दल ने इस मामले में पहल नहीं की। देश के अलग–अलग

हिस्सों में सांसद निधि के आबंटन और इस्तेमाल को लेकर अलग तरह की रिपोर्ट आ रही है। जहां कुछ इलाकों में इस निधि से वाकई जन उपयोगी काम हुए हैं, वहीं ज्यादातर इलाकों में इसके आबंटन और इस्तेमाल को लेकर तमाम तरह की निराशाजनक बातें सामने आ रही हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य हिस्सों में भी ऐसे दलाल विकसित हो गए हैं जो किसी भी योजना के लिए सांसद निधि या विधायक निधि से धन आबंटन करवाने का ठेका लेते हैं। ये लोग सांसदों के इस कोष पर सतर्क निगाह रखते हैं। इन्हें पता होता है कि किस इलाके के कौन से सांसद का कोष इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्हें यह भी पता होता है कि कौन से सांसद या विधायक से सरलता से किसी भी प्रोजैक्ट के लिए धनराशि का आबंटन करवाया जा सकता हैं। ये लोग बाकायदा एक मोटे कमीशन के चक्कर में इस काम को करवाने के लिए तत्पर रहते हैं।

चूंकि इस तरह की कमीशनबाजी का लेन–देन काले धन से गुपचुप तरीके से होता है, इसलिए इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। वैसे भी इस मामले में किसी भी पक्ष के शोर मचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। दलाल जन–प्रतिनिधियों से सम्पर्क करके इस धनराशि से कालोनी की सड़कें और स्कूल कालेजों की इमारतें बनवाने लगे। जहां से भी उन्हें भारी कमीशन की राशि मिल सकती थी वे वहां इसका उपयोग करने लगे। हालांकि सभी सांसद और विधायक ऐसा नहीं करते हैं।

कई सांसदों और विधायकों ने इस धनराशि का बेहतर उपयोग किया है और विकास कार्य भी कराये हैं। लेकिन इस धनराशि से कमीशन लेने वाले सांसदों और विधायकों की संख्या भी कम नहीं है।

महालेखा परीक्षक ने 1998 में ही इस फंड के भारी दुरूपयोग की रपट सरकार को दे दी थी। इसीलिए जब इसे एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया तो 10 मार्च 2003 को राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता मनमोहन सिंह ने अटल सरकार से यह कहा कि 'यदि आप चीजों को इसी रास्ते जाने देंगे तो जनता नेताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खो देगी' वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने करीब दो साल पहले केंद्र सरकार से यह भी सिफारिश की कि वह सांसद विधायक निधि समाप्त कर दे। इसके बावजूद मनमोहन सरकार यह काम आज तक नहीं कर सकी। मोइली आयोग की रपट पर भाकपा महासचिव एबी वर्धन ने कहा था कि 'वाम दल शुरू से ही इस योजना के विरोधी रहे हैं'।

केन्द्र सरकार ने 23 दिसम्बर 1993 को एक ऐसी योजना की शुरूआत की जिसके तहत संसद सदस्यों को विकास परियोजनाओं की सिफारिश करने की अनुमति मिली। ये परियोजनाएं इस तरह की हैं कि उनसे टिकाऊ सामुदायिक संपदा और बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है। इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी एमपीलैड्स का नाम दिया गया।

मार्च 2009 तक सरकार इस योजना के तहत 19,426 करोड़ रूपये जारी कर चुकी है। दरअसल यह फंड सन् 1993 में तब शुरू किया गया, जब नरसिंह राव मंत्रिमंडल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था। उस सरकार को अनेक सांसदों को खुश करना था। इस संबंध में संयुक्त संसदीय समिति ने 23 दिसम्बर 1993 को करीब 4 बजे अपनी सिफारिश सदन में पेश की और सरकार ने उसी दिन छह बजे उस सिफारिश को स्वीकार कर लेने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी। जिस सरकार को कंधार विमान अपहरण और मुम्बई हमले की सूचना मिल जाने के बाद भी समय पर त्वरित कार्रवाई करने की चिंता नही होती, वह सरकार इस मामले में दो घंटे के भीतर ही निर्णय कर लेती है। बाद में राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी व्यवस्था की गयी।

सालाना विधायक निधि देने वाले राज्य हैं– झारखण्ड (तीन करोड़), दिल्ली (दो करोड़), उ.प्र. (दो करोड़), महाराष्ट्र (डेढ़ करोड़), तमिलनाडु (डेढ़ करोड़) मध्य प्रदेश (एक करोड़), बिहार (एक करोड़), छत्तीसगढ़ (एक करोड़), उत्तराखण्ड (सवा करोड़), राजस्थान (पचास लाख), केरल (पचीस लाख), हिमांचल प्रदेश (पचीस लाख), उत्तर पूर्व राज्य (दस से पचीस लाख)।

सोचने वाली बात यह है कि जिस देश की आधी से अधिक आबादी बेहद गरीबी और बदहाली में जी रही है उस देश में जनता के सीमित संसाधनों को फालतू के कामों में दुरूपयोग करना कहां की बुद्धिमानी है। इसलिए इस व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

नीतीश ने बिहार से इसकी शुरूआत की है और अब मनमोहन सिंह को सांसद निधि को खत्म करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि हमारे सांसदों और विधायकों का चरित्र जनता के लिए प्रेरक बन सके। ❑

नेक उद्यमी पर भी सरकार का अंकुश जरूरी

समस्या है कि जब सरकार स्वयं ही उद्यमी की गिरफ्त में हो तो उसके कारनामों का निष्पक्ष विवेचन कौन करेगा? अतः वह व्यवस्था दोष पूर्ण है जिसमें उद्यमी सरकार पर हावी हो जाये और उसके कार्यों को जनहित की कसौटी पर तौला ही न जाये। यह बात बिड़ला, अम्बानी और स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त कंपनियों – सभी पर लागू होती है। सरकार की अहं जिम्मेदारी है कि उद्यमियों से उपर उठकर उनके कार्य कलापों पर नजर रखे और उन्हें जनहित की दिशा में ढकेले।

■ डा. भरत झुनझुनवाला

स्पेक्ट्रम घोटाले ने स्पष्ट कर दिया है कि उद्यमियों, मंत्रियों एवं अधिकारियों की मिली–भगत से नियम–कानूनों का उल्लंघन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये किये जा रहे हैं।

यह नई कहानी नहीं है। 1967 में मुम्बई यूनिवर्सिटी द्वारा प्लानिंग कमीशन की दी गयी रपट में बताया गया था कि 1957 से 1966 के बीच जारी समस्त औद्योगिक लाइसेंस में से 20 प्रतिशत बिड़ला समूह को दिये गये थे। पिछले दशक में अम्बानी समूह की भी ऐसी ही कहानी है। इस समूह की पैठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता दल सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद प्रधान मंत्री देवेगौड़ा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये बंगलूरू की यात्रा धीरूभाई अम्बानी के निजी वायुयान से की थी। परंतु उद्यमियों की इस पैठ को पूर्णतया गलत नहीं ठहराया जा सकता है। जब सरकार जड़ एवं कुंठित हो तो भ्रष्टाचार मोबिल आयल का कार्य करता है।

उद्यमी के लिये भ्रष्टाचार का सामना करना महंगा पड़ता है। किसी फैक्ट्री के बायलर का मुआयना किया जाना था। इंस्पेक्टर ने स्वीकृति देने के लिये बीस हजार रुपये की पूर्णतया नाजायज घूस की मांग की। उद्यमी महोदय अड़ गये। परिणामस्वरूप इंस्पेक्टर ने बायलर को फेल कर दिया। तब उद्यमी महोदय दौड़े भागे, उच्च अधिकारियों को शिकायत की, दूसरे इंस्पेक्टर को बुलवाया और बायलर को पास कराया। इस दौड़ भाग में बीस हजार से ज्यादा खर्च हो गये। एक सप्ताह तक कारखाना बन्द पड़ा रहा और कम्पनी को भारी घाटा लगा सो अलग से। ऐसी परिस्थितियों में उद्यमी द्वारा भ्रष्टाचार को गलत नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु इसी भ्रष्टाचार का उपयोग दूसरों को कुचलने और अनैतिक आय अर्जित करने में किया जाने में अन्तर है।

पिछले दो दशक में अम्बानी समूह के शीर्ष पर पहुंचने में नेताओं एवं अधिकारियों को खरीदने की अहं भूमिका रही है। हैमिश मैक्डानल्ड ने हाल में प्रकाशित पुस्तक 'अम्बानी एंड संस' में कई रोचक वृत्तान्त बताये हैं। सिंथेटिक कपड़ों को पालिएस्टर फिलामेंट यार्न से बनाया जाता है। सत्तर के दशक में भारत में पालिएस्टर

पिछले दो दशक में अम्बानी समूह के शीर्ष पर पहुंचने में नेताओं एवं अधिकारियों को खरीदने की अहं भूमिका रही है। हैमिश मैक्डॉनल्ड ने हाल में प्रकाशित पुस्तक 'अम्बानी एंड संस' में कई रोचक वृत्तांत बताये हैं।

यार्न की शार्टेज थी। इसका मूल्य विश्व बाजार की तुलना में सातगुना था। तब धीरूभाई ने वित्तमंत्री टी. ए. पाई से नायलान कपड़ों के निर्यात के सामने पालिएस्टर यार्न के आयातों की छूट स्वीकृत करा ली। धीरूभाई ने नायलान कपड़ों के आयात का स्वांग रचा। जो माल विश्व बाजार में दो रूपये में नहीं बिकता था उसे चार रूपये में बिका हुआ दिखाया। ऊंचे मूल्य पर बिक्री दिखाकर अधिक पालिएस्टर को आयात करने का परमिट लिया। आयातित पालिएस्टर यार्न को सात गुना दाम पर बेच कर भारी लाभ कमाया। परन्तु चार रूपये के मूल्य पर नायलान कपड़ा विश्व बाजार में नहीं बिक सकता था। अतः इसे वास्तव में सस्ते मूल्य पर बेचा अथवा समुद्र में फेंक दिया अथवा बंदरगाह पर छोड़कर सड़ने दिया। चार रूपये के इस नुकसान के सामने यार्न की बिक्री से लाभ बहुत ज्यादा था।

1982 में रिलायंस की पलिएस्टर बनाने की पाताल गंगा फैक्ट्री चालू हो गयी। मात्र तीन सप्ताह बाद सरकार ने पालिएस्टर यार्न के आयात पर 15,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त आय कर लगा दिया। तदानुसार पालिएस्टर यार्न के मूल्य में भारी वृद्धि हुयी। पाताल गंगा द्वारा उत्पादित पालिएस्टर यार्न के दाम भी इतने ही बढ़ गये और रिलायंस को भारी लाभ हुआ। परन्तु इस महंगाई का खामियाजा उन 150 छोटी कम्पनियों को भरना पड़ा जो इसे खरीदते थे।

इन कम्पनियों ने विज्ञापन निकालकर सरकार का ध्यान दिलाया कि उनका धंधा चौपट हो रहा है किन्तु सरकार ने उनकी सुध न ली।

1995 में हर्षद मेहता प्रकरण के दौरान मुम्बई स्टाक एक्सचेंज को ज्ञात

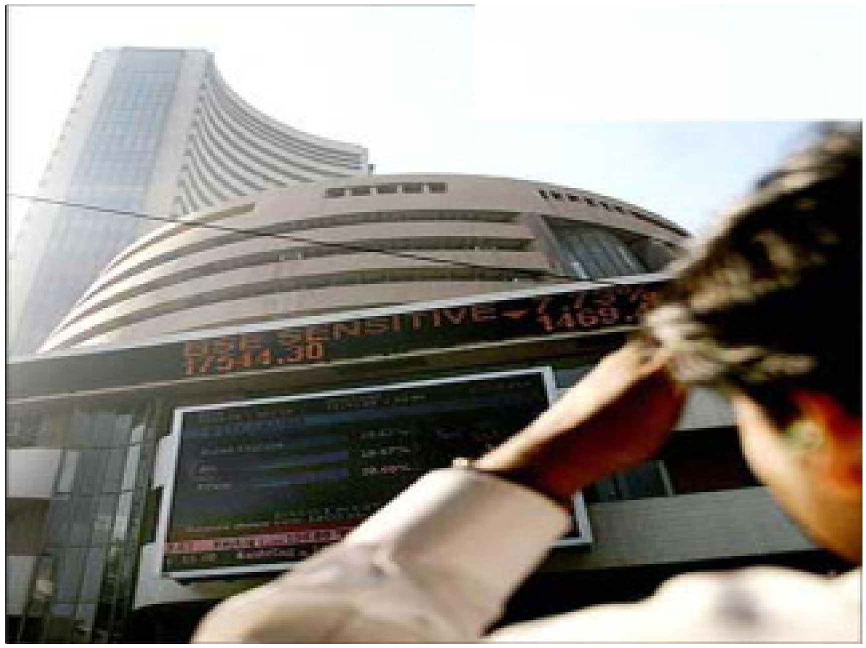

हुआ कि रिलायंस द्वारा एक ही नम्बर के शेयर के दो स्क्रिप्ट जारी किये जा रहे थे। रिलायंस ने अपनी गलती स्वीकार की और विवादित शेयरों के एवज में नये शेयर स्क्रिप्ट जारी किये। इन गैर कानूनी कृत्यों के लिये रिलायंस के मालिकों को दंडित नहीं किया गया।

2005 में इराक में संयुक्त राष्ट्र की तेल के बदले अनाज की योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। भारतीय कम्पनियों मे सद्दाम हुसैन से सर्वाधिक तेल रिलायंस ने खरीदा था। परन्तु अम्बानी बन्धुओं की सांसदों के बीच पकड़ इतनी गहरी थी कि चर्चा में एक भी सांसद ने रिलायंस का नाम नहीं लिया।

स्पष्ट होता है कि अम्बानी समूह ने सरकारी अधिकारियों एवं मंत्रियों को खरीद रखा था और नियमों को अपने पक्ष में बदलवाया जाता था। सुखद परिणाम यह हुआ कि रिलायंस के साथ–साथ इसके शेयर धारकों भारी मुनाफा हुआ। धीरूभाई की मृत्यु पर आम जनता का जो अपार जनसमूह उमड़ा था उसके पीछे यही लाभ था। एक सामान्य अध्यापक से धीरूभाई ने देश की सबसे बड़ी कम्पनी स्थापित करने में सफलता पाई। उन्होंने सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अपने बड़े से बड़े सपने को साकार कर सकता है। देश के विकास में अम्बानी बन्धुओं का बड़ा योगदान रहा।

अम्बानी समूह ने सरकारी अधिकारियों एवं मंत्रियों को खरीद रखा था और नियमों को अपने पक्ष में बदलवाया जाता था। सुखद परिणाम यह हुआ कि रिलायंस के साथ–साथ इसके शेयर धारकों को भारी मुनाफा हुआ। धीरूभाई की मृत्यु पर आम जनता का जो अपार जनसमूह उमड़ा था उसके पीछे यही लाभ था।

हमारे सामने दो परस्पर अर्न्तविरोधी निष्कर्श सामने आते हैं। एक ओर अम्बानी समूह ने नियमों को तोड़ मरोड़ कर देश के तमाम छोटे मोटे उद्योगों को समाप्त किया जैसा कि पालिएस्टर यार्न पर 15,000 रुपये प्रति टन का आयात कर लगवा कर। दूसरी तरफ उन्होंने लाखों

शेयर धारकों को अमीर बनाया। इन परस्पर विरोधी तत्वों में से किसे प्राथमिकता दी जाये?

शेयर धारकों को लाभ पहुंचाने और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने में धीरूभाई का मूल उद्देश्य लाभ कमाना मात्र था। मुकेश अम्बानी के नये निवास का मासिक बिजली का बिल 70 लाख रुपये है। ऐसा विकृत दिखावा कदापि देश हित में नहीं हो सकता है। उन्होंने पालिएस्टर यार्न का उपयोग करने वाले सम्पूर्ण उद्योग को नष्ट कर दिया और उनके मालिकों को चोट पहुंचायी। उन्हें सद्दाम हुसैन से विवादित तेल खरीदने में संकोच नहीं हुआ चूंकि उनका उद्देश्य तो मात्र लाभ कमाना था। संभवतया धीरूभाई के कारनामों से देश को नुकसान अधिक और लाभ कम हुआ हो। इस लाभ हानि का मूल्यांकन सरकार को ही करना होगा।

समस्या है कि जब सरकार स्वयं ही उद्यमी की गिरफ्त में हो तो उसके कारनामों का निष्पक्ष विवेचन कौन करेगा? अतः वह व्यवस्था दोष पूर्ण है जिसमें उद्यमी सरकार पर हावी हो जाये और उसके कार्यों को जनहित की कसौटी पर तौला ही न जाये। यह बात बिड़ला, अम्बानी और स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त कंपनियों – सभी पर लागू होती है। सरकार की अहं जिम्मेदारी है कि उद्यमियों से उपर उठकर उनके कार्य कलापों पर नजर रखे और उन्हें जनहित की दिशा में ढकेले। सरकार की अकर्मण्यता के बावजूद यदि संयोगवश अम्बानी समूह ने कुछ जनहित स्थापित किया तो भी इसे माडल के रूप में स्वीकार करना घातक होगा। भविष्य में इस कार्य शैली का दुरुपयोग देश को गर्त में ढकेलने के लिये किया जा सकता है। धीरूभाई ने सरकार पर अपने कब्जे का उपयोग धन कमाने के लिये किया। अतः अब कोई भी उद्यमी इसी प्रकार का उपयोग देश को बेचने के लिये भी कर सकता है। अतः सरकार पर उद्यमी के अंकुश को मान्यता नहीं देनी चाहिये वरन् सरकार का अंकुश उद्यमी परा होना चाहिये। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति

महिलाएं जिस तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रही है, इसकी पचास वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की गई थी। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और माता–पिता भी नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें। स्वतंत्रता के पश्चात् शासन के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। ये इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सन् 1882 में भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या 2,054 की ही थी जो लिख पढ़ सके...

■ रेणु पुराणिक

स्वतंत्रता के पश्चात् वर्तमान काल में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रो. एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण एवं जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके साथ शिक्षा के प्रसार तथा औद्योगीकरण ने इन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर दिए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाओं ने आज भारतीय जीवन के परंपरागत सिद्धांतों को केवल अस्वीकार ही नहीं किया है अपितु उसे चुनौती दी है। वह भी इस रूप में कि वे उन सिद्धांतों को परिवर्तित करके रहेगी, जो उनकी सामाजिक स्थिति गिराने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। इसके परिणामस्वरूप आज महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए है।

स्वतंत्रता के पश्चात् वर्तमान काल में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रो. एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण एवं जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके साथ शिक्षा के प्रसार तथा औद्योगीकरण ने इन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर दिए हैं।

अर्थात् महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर से कम होने लगी और उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलने लगे। महिलाओं ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाचार–पत्र, संचार–साधन एवं पत्र–पत्रिकाओं को माध्यम के रूप में अपनाया। सामाजिक एवं पारिवारिक अधिकारों में संयुक्त परिवारों के विघटन के साथ–साथ वृद्धि होती गई। सामाजिक अधिनियमों ने एक ऐसे समाज को जन्म दिया, जिसमें बाल–विवाह, दहेज प्रथा, अंतर्जातीय विवाह जैसी समस्याओं का निदान संभव हो गया।

महिलाओं में शिक्षा का प्रसार

महिलाएं जिस तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रही है, इसकी पचास वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की गई थी। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और माता–पिता भी नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें। स्वतंत्रता के पश्चात् शासन के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। ये इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सन् 1882 में भारत में ऐसी

महिलाओं की संख्या 2,054 की ही थी जो लिख पढ़ सके। परंतु सन् 1971 की मतगणना की रिपोर्ट के अनुसार साक्षर महिलाओं की संख्या लगभग 4 करोड़ 93 लाख हो गई। जहां पहली बार सन् 1882 में एक महिला ने स्नातक की उपाधि ली, वहीं सन् 1981 में 65 लाख से भी अधिक लड़कियां विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर कक्षाओं में सभी विषयों में शिक्षा ग्रहण कर रही थी।

वर्तमान काल में कला, विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला, पाक कला एवं संगीत आदि की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध है। मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों में लड़कियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान काल में मेडिकल कालेज तथा औद्योगिक व व्यवसायिक कालेजों में कुल विद्यार्थियों में 24 प्रतिशत लड़कियां पढ़ रही हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। विश्वविद्यालय तथा कालेजों में इनका 16 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं का मानसिक स्तर पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है।

आर्थिक जीवन में बढ़ती स्वतंत्रता

रूढ़िवादी लोग आज की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। वे इसे अच्छा नहीं मानते हैं। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा, औद्योगीकरण और नवीन विचार–धारा के कारण पुरुषों पर से महिलाओं की आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। निम्न वर्ग की बहुत–सी महिलाएं स्वतंत्रता के पूर्व भी उद्योगों एवं अन्य घरेलू कार्यों के द्वारा जीविका उपार्जित करती थी। परंतु उस समय उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाओं द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध था।

वर्तमान काल में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिलाओं में शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया है। आजकल शिक्षा, चिकित्सा उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, मनोरंजन आदि अनेकों क्षेत्रों के कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ रही हैं। वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका उपार्जित कर रही हैं। आज महिलाओं में आत्म–विश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में जो प्रगति हुई है, वह उनको मिली आर्थिक स्वतंत्रता का ही परिणाम है।

परिवार में महिलाओं के इन बढ़ते अधिकारों से कुछ लोग चिंतित हो उठे है। पारिवारिक जीवन के विघटित हो जाने पर, उनकी चिंता का कारण उनके एकाधिकार में होती जा रही कमी है। आज की नई पीढ़ी महिलाओं को उनके पारिवारिक अधिकार देना चाहती है और वे यह नहीं चाहते हैं कि किसी कारणवश महिलाए अपने अधिकारों से वंचित रह जाए।

पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि

महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में वर्तमान काल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसे पुरुष पहले अपनी सेविका तथा अपनी संपत्ति मानता था, वही आज उसका सहयोगी और मित्र बन गया है। आज महिला परिवार में एक प्रबंधक है न कि याचिका। आजकल शिक्षित महिला किसी की स्थिति में अपने अधिकारों का बलिदान करके, संयुक्त परिवार में रहकर शोषित होना नहीं चाहती है। बल्कि उसने एक स्वतंत्र एकाकी परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्णतः उपयोग करने का प्रयास किया है।

महिलाओं की इच्छा का महत्व बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय के उपभोग, संस्कारों का प्रबंध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज महिलाए अपने पारिवारिक अधिकारों के लिए अंतर्जातीय विवाहों को प्राथमिकता दे रही है। वर्तमान में महिलाएं विलम्ब से विवाह करने पर जोर दे रही हैं।

परिवार में महिलाओं के इन बढ़ते अधिकारों से कुछ लोग चिंतित हो उठे है। पारिवारिक जीवन के विघटित हो जाने पर, उनकी चिंता का कारण उनके एकाधिकार में होती जा रही कमी है। आज की नई पीढ़ी महिलाओं को उनके पारिवारिक अधिकार देना चाहती है और वे यह नहीं चाहते हैं कि किसी कारणवश महिलाए अपने अधिकारों से वंचित रह जाए।

राजनैतिक चेतना में वृद्धि

आज राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में जिस प्रकार उन्नति हो रही है और यह जिस तेजी से ऊचांईया छू रही है, वह एक आश्चर्य का विषय है। सन् 1937 में 41 सुरक्षित सीटों पार केवल 10 महिलाएं ही चुनाव में आगे आई थी, जबकि विधानसभाओं में सन् 1957 में 105 महिलाएं विधानसभा सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुई। सन् 1977 के आम चुनाव के पश्चात् लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल मिलाकर 42 महिलाएं थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब संपूर्ण विश्व विशेषकर पश्चिम तथा सभ्य समाज की महिलाए आश्चर्य चकित रह गई। उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि उनकी राजनीतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। भारत के अनेक राज्यों में महिला मुख्यमंत्री का होना आश्चर्य की बात थी। मध्यकाल की रूढ़ियों को समाप्त करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं ने अपनी राजनैतिक शक्ति का पूरा–पूरा सदुपयोग किया जो प्रशंसनी है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं विपक्ष नेता के पद पर महिलाएं ही आसीन है। यह भारतीय महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है।

सामाजिक जागरूकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तना आ गए है। आज उन परिवारों में भी महिलाये खुली हवा में श्वांस ले रही है जहां कुछ वर्ष पूर्व तक अकेले बाहर निकलना दुभर था और पर्दे में रहना पड़ता था। मध्यकाल की उन रूढ़ियों के प्रति उदासीनता निरंतर बढ़ती जा रही है जिन्हें कभी महिलाए अज्ञानतावश अपना आर्दश मानती थी। महिलाए उन सामाजिक बंधनों से ही धीरे–धीरे मुक्त होने लगी है, जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों में जकड़कर रखा था। भारतीय महिलाओं की स्थिति में होने वाला परिवर्तन निश्चय ही महत्वपूर्ण है। कट्टरपंथी एवं पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचारों में भी अब बदलाव आने लगा है। परंतु महिलाओं में होने वाले इन सुधारों एवं परिवर्तनों को कुछ पुरुष वर्ग अच्छा नहीं समझते हैं।

महिलाएं सबसे अधिक शांति प्रिय एवं सहनशील मानी जाती रही है, इन्होंने ही अब अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिकारों की मांग करना आरंभ कर दिया है। जो समानता का दावा भारतीय महिलाओं द्वारा आज किया जा रहा है. . .

उनका कहना है कि महिलाओं को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार मिलने से समाज में अंतर्जातीय विवाह, विलम्ब से विवाह, विवाह–विच्छेद, अनैतिकता, संस्कारहीनता, शिक्षित लड़कियों के विवाह की समस्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे समाज का विघटित होने का भय बना रहता है। उनकी यह धारणा भ्रमपूर्ण है। चूंकि ये सभी परिस्थितियां पुरुषों के 'अहम्' के विरूद्ध हो सकती है। परंतु इन परिवर्तनों में महिला वर्ग का हित निहित है। समाज की बदलती हुई आवश्यकता के प्रति उनमें जागरूकता आ रही है।

महिलाएं सबसे अधिक शांति प्रिय एवं सहनशील मानी जाती रही है, इन्होंने ही अब अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिकारों की मांग करना आरंभ कर दिया है। जो समानता का दावा भारतीय महिलाओं द्वारा आज किया जा रहा है, उसको देखते हुए इन न्याय–संगत अधिकारों के मान लेने से ही भारतीय समाज का पुर्नजीवन संभव है।

परंपरागत भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भारतीय समाज की महिलाओं की वर्तमान स्थिति में अनेक परिवर्तन आए हैं। महिला शिक्षा, रहन–सहन, वेश–भूषा और अधिकारों में विशेषतः परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूलस्वरूप पूर्णरूप से परिवर्तित हो गया हो, ऐसा नहीं है। भारतीय समाज अनेक परिवर्तनों एवं प्रभावों के बाद भी अपनी मौलिक विशेषताओं को संभालकर रखने में सफल रहा है। ❑